page 1_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/3/2026 12:38 AM Page 1

देहात संदेश वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-164 जम्मू तवी, शुक्रवार 03 जुलाई, 2026 मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये

सत्यमेव जयते

पवित्र अमरनाथ धाम की ओर श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति की पावन यात्रा

श्री अमरनाथ जी
यात्रा-2026

यात्री क्या करें

- प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना एवं वैध RFID कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है।
- यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व जम्मू/श्रीनगर के निधारित केंद्रों से अपना RFID कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।
- RFID कार्ड प्राप्त करते समय अपने आधार कार्ड का विवरण साथ रखें।
- यात्रा के दौरान सुरक्षा हेतु RFID कार्ड को हमेशा अपने गले में पहनकर रखें।
- पर्याप्त गर्म ऊनी कपड़े, छाता, विंडचीटर, रेनकोट एवं वाटरप्रूफ जूते साथ रखें। मौसम अनिश्चित रहता है तथा तापमान अचानक 5°C से नीचे गिर सकता है।
- खड़ी एवं कठिन चढ़ाई वाले रास्तों पर धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक चलें, जल्दबाजी न करें।
- थकान से बचने के लिए समय-समय पर विश्राम करते रहें।

यात्री क्या न करें

- अनिवार्य पंजीकरण एवं वैध RFID कार्ड के बिना कोई भी यात्री यात्रा प्रारंभ न करें।
- ऊँचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
- शराब, कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन न करें और धूम्रपान से बचें।
- चेतावनी संकेत वाले स्थानों पर न रुकें।
- यात्रा मार्ग में शॉर्टकट न अपनाएँ, यह जोखिम भरा हो सकता है।
- यात्रा क्षेत्र की स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण को नुकसान न पहुँचाएँ।
- अपने समूह से अलग न हों, हमेशा अपने साथियों के साथ रहें।

आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो !

DIP/J-4901/26
Dtd: 2-7-2026

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट एक्सेस करने के लिए स्कैन करें

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार

@informationprjk Information & PR, J&K @diprjk @dipr_jk

शानदार करियर के लिए 12वीं साइंस के बाद करें ये कोर्स

साइंस स्ट्रीम से 12वीं करने के बाद अकसर स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर तो बनना नहीं चाहते लेकिन उन्हें इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी समझ में नहीं आता है और करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. असल में साइंस एक बहुत बड़ी स्ट्रीम हैं जिसमें एक या दो नहीं बल्कि ढेरों विकल्प मौजूद हैं. हम यहां पर आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं जो आपको अपने करियर में एक अलग मुकाम हासिल करने में मदद करेंगे:

नैनो-टेक्नोलॉजी:
ग्लोबल इनफॉर्मेशन इंक की रिसर्च के मुताबिक, 2018 तक नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. नैस्कॉम के मुताबिक 2015 तक इसका कारोबार 180 अरब डॉलर से बढ़कर 890 अरब डॉलर हो जाएगा. ऐसे में इस फील्ड में 10 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. 12वीं के बाद नैनो टेक्नोलॉजी में बीएससी या बीटेक और उसके बाद इसी सब्जेक्ट में एमएससी या एमटेक करके इस क्षेत्र में शानदार करियर बनाया जा सकता है

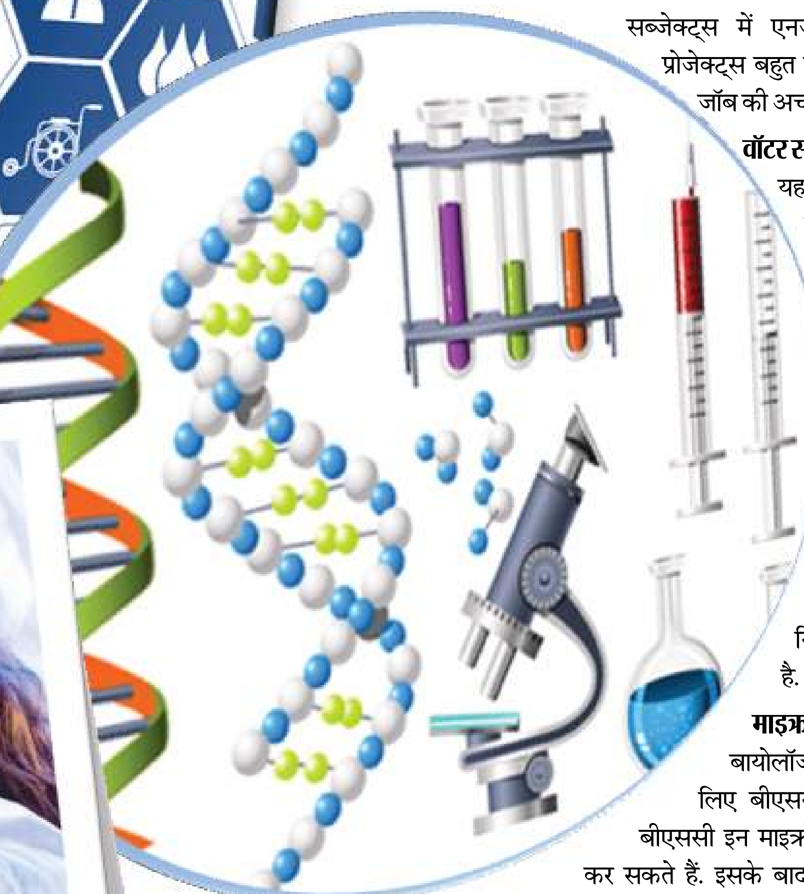

स्पेस साइंस: यह बहुत ब्रॉड फील्ड है. इसके तहत कॉस्मोलॉजी, स्टेलर साइंस, प्लैनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई फील्ड्स आते हैं. इसमें तीन साल की बीएससी और चार साल के बीटेक से लेकर पीएचडी तक के कोर्सेज खास तौर पर इसरो और बेंगलुरु स्थित IISC में कराए जाते हैं.

एस्ट्रो-फिजिक्स: अगर आप सितारों और गैलेक्सी में दिलचस्पी रखते हैं तो 12वीं के बाद एस्ट्रो-फिजिक्स में रोमांचक करियर बना सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो पांच साल के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम (एमएस इन फिजिकल साइंस) और चार या तीन साल के बैचलर्स प्रोग्राम (बीएससी इन फिजिक्स) में एडमिशन ले सकते हैं. एस्ट्रोफिजिक्स में डॉक्टरेट करने के बाद स्टूडेंट्स इसरो जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बन सकते हैं

एनवायर्नमेंटल साइंस: इस स्ट्रीम में पर्यावरण पर इंसानी गतिविधियों से होने वाले असर का अध्ययन किया जाता है. इसके तहत इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. इन सभी सब्जेक्ट्स में एनजीओ और यूएनओ के प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में जॉब की अच्छी संभावनाएं हैं.

वॉटर साइंस:
यह जल की सतह से जुड़ा विज्ञान है. इसमें हाइड्रोमिटियोरोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट, वॉटर क्वॉलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोइंफॉर्मेटिक्स जैसे विषयों की पढ़ाई करनी होती है. हिमस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए इस फील्ड में रिसर्चर्स की डिमांड बढ़ रही है.

माइक्रो-बायोलॉजी: माइक्रो-बायोलॉजी की फील्ड में एंट्री के लिए बीएससी इन लाइफ साइंस या बीएससी इन माइक्रो-बायोलॉजी कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद मास्टर डिग्री और पीएचडी भी का ऑप्?शन भी है. इसके अलावा पैरामेडिकल, मरीन बायोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, फिशरीज साइंस जैसे कई फील्ड्स हैं, जिनमें साइंस में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स अच्छा करियर बना सकते हैं.

डेयरी साइंस:
डेयरी प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत अहम देश है. भारत डेयरी प्रोडक्शन में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है. डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस के तहत मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रिब्यूशन की जानकारी दी जाती है. भारत में दूध की खपत को देखते हुए इस क्षेत्र में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढने लगी है. साइंस सब्जेक्ट से 12वीं करने के बाद स्टूडेंट ऑल इंडिया बेसिस पर एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद चार वर्षीय स्नातक डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट डेयरी टेक्नोलॉजी में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर करते हैं.

रोबोटिक साइंस:
रोबोटिक साइंस का क्षेत्र काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इसका इस्तेमाल इन दिनों तकरीबन सभी क्षेत्रों में होने लगा है. जैसे- हार्ट सर्जरी, कार असेम्बलिंग, लैंडमाइंस. अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इस क्षेत्र से जुड़े कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हैं. जैसे ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स सिस्टम. कम्प्यूटर साइंस से स्नातक कर चुके स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए योग्य माने जाते हैं. रोबोटिक में एमई की डिग्री हासिल कर चुके स्टूडेंट्स को इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में रिसर्च वर्क की नौकरी मिल सकती है.

अगर टेलीविजन में बनाना चाहते हैं करियर...

हमारे समाज और घर-परिवार में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे टेलीविजन की वर्किंग स्टाइल और किरदार पसंद न आते हों लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पसंदीदा टेलीविजन को करियर के तौर पर भी चुन सकते हैं. मीडिया और टेलीविजन के बढ़ते प्रभाव के बीच आपके पास ऐसे कई मौके हैं कि आप इसमें करियर बना कर मोटी कमाई कर सकते हैं.

इसके मद्देनजर आज मास कम्यूनिकेशन इन टीवी जर्नलिज्म में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जैसे कोर्सेस शुरू हुए हैं. ऐसे कोर्सेस आप कई बहुप्रतिष्ठित संस्थानों व विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं. साथ ही दिल्ली के भारतीय विद्या भवन जैसे संस्थान भी कई डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं.

इन कोर्सेस को करने से आप टेक्निकली दूसरे सामान्य उम्मीदवारों से आगे चले जाते हैं. यहां हम आपके लिए उन तमाम कोर्सेस के नाम सुझा रहे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिप्लोमा
वीडियो कैमरा व लाइटिंग में डिप्लोमा
वीडियो एडिटिंग व साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा
प्रोफेशनल फोटोग्राफी में डिप्लोमा
एनिमेशन फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा wD, xD, & VFX
IT और वेब डिजाइनिंग में डिप्लोमा
छ्ङ्मक्कऔर ग्राफिक्स में डिप्लोमा

गौरतलब है कि यहां से डिप्लोमा हासिल करना बाजार और तमाम संस्थानों की तुलना में सस्ता भी है और सहूलियत भी है.

कॉरपोरेट वर्ल्ड के लीगल कंसल्टेंट

एक समय ऐसा था, जब लॉयर्स को केवल कोर्ट रूम में जिरह करते हुए प्रोफेशनल्स के तौर पर देखा और जाना जाता था, लेकिन हाल के वर्षो में इस फील्ड में काफी चेंज आया है और नए-नए एरिया भी जुड़ते जा रहे हैं। इस फील्ड में आने वाले अवारों को देखते हुए स्टूडेंट्स का रुझान 'कॉरपोरेट लॉ' की तरफ खूब देखा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने इस फील्ड की चमक को और बढ़ाया है। आप इस फील्ड में आते हैं, तो यहां नेम-फेम के अलावा, प्रोफेशनल्स की सैलरी भी काफी अच्छी होती है।

क्वालिफिकेशन

एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी की
एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर प्रियंका गोयल के मुताबिक, इस फील्ड में एंट्री के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला, 12वींके बाद स्टूडेंट्स देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराके लॉयर बन सकते हैं। दूसरा,
किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद तीन वर्षीय लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।

लॉ से संबंधित एग्जाम

लॉ इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्लीयर करना पड़ता है। कुछ एंट्रेंस **एग्जाम इस तरह हैं..**

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट : इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लैट के नाम से भी जाना जाता है। यह नेशनल लेवल का लॉ एग्जाम है। इसके जरिए देश की टॉप-14 लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया जा सकता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में आमतौर पर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट : इसे एलसेट के नाम से भी जाना जाता है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, यूपीईएस देहरादून, आईटीएम गुड़गांव आदि जैसे देश के करीब 60 लॉ कॉलेजों में इस एग्जाम के जरिए एंट्री मिलती है। इस एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

डीयू एलएलबी/एलएलएम : दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इसके जरिए एलएलबी और एलएलएम जैसे कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है।

एसईटी सिंबायोसिस : इस एंट्रेंस टेस्ट के जरिए सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले लॉ इंस्टीट्यूट के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है।

यूएलएसएटी : यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऐंड एनर्जी स्टडी यूएलएसएटी आयोजित करती है। इस टेस्ट में पास होने के बाद बैचलर ऑफ लॉ, कॉरपोरेट लॉ, साइबर लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एलएलबी किया जा सकता है।

कॉरपोरेट लॉयर

यह लीगल सर्विसेज का उभरता हुआ फील्ड है। कॉरपोरेट लॉयर्स की जरूरत कंपनीज के लीगल डिपार्टमेंट में होती है। यहां जूनियर कॉरपोरेट लॉयर के रूप में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की ड्रॉफ्टिंग, फाइल की तैयारी, मेमोरेंडम तैयार करना, सिक्योरिटी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स तैयार करना होता है। इसके अलावा, लेबर इश्यू, एम्प्लॉयीज राइट्स, अमैलगमेशन, स्प्लिट से रिलेटेड वर्क भी इन्हींके जिम्मे होता है। बड़े बिजनेस हाउसेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी कई जटिल कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें हल करने के लिए कॉरपोरेट लॉयर्स की मांग बढ़ रही है। इनका कार्य कंपनी के संचालन में कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कंपनी से जुड़े मुकदमों की पैरवी आदि करना होता है। अगर संक्षेप में कहें, तो इनके कार्य को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, बिजनेस से संबंधित लीगर इश्यू के बारे में सलाह देना। दूसरा, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की ड्रॉफ्टिंग। तीसरा, लॉ और रेगुलेशन का अनुपालन करना। हालांकि कॉरपोरेट लॉयर्स एक से अधिक एरिया में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, जैसे- टैक्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आदि।

वर्क ऑप्शंस

आज कॉरपोरेट लॉयर्स की डिमांड बिजनेस हाउसेज के अलावा लॉ फर्म्स में भी खूब हैं। इसके अलावा, इनके लिए टीचिंग का ऑप्शन भी खुला रहता है। इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स इंवेस्टमेंट बैंकिंग में भी करियर बना सकते हैं। कॉरपोरेट हाउसेज के अलावा, बड़ी अकाउंटिंग फर्म, जैसे- प्राइसवाटरहाउसकूपर्स और केपीएमजी में भी करियर की तलाश कर सकते हैं। साथ ही, कई बड़ी ग्लोबल लॉ फर्म भी भारत आने को तैयार है। यहां भी कॉरपोरेट लॉयर्स के लिए कार्य करने का अच्छा मौका हो सकता है। इन दिनों कॉरपोरेट लॉयर्स की डिमांड केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी जबरदस्त है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कॉरपोरेट लॉयर्स की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि वहां की तुलना में भारतीय लीगल प्रोफेशनल्स की फीस कम होती है।

सैलरी पैकेज

इस फील्ड में फ्रेशर्स 3-12 लाख रुपये सालाना सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा सैलरी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड और कंपनी पर भी डिपेंड करता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

epaper.dehatsandesh.com

5 विंबलडन - जोकोविच ने सितसिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में बनाई जगह

6 जीएसटी संग्रह जून मे13.9 प्रतिशत बढकर 1.94 लाख करोड रूपय रहा

8 डोर-टू-डोर मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य जांच

मौसम जम्मू — न्यूनतम 24 — अधिकतम 34

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-164 | जम्मू तवी, शुक्रवार 03 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

उपराज्यपाल सिन्हा ने 4,822 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया

जम्मू, 02 जुलाई । श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा गुरुवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गई। जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि कुल 4,822 तीर्थयात्री 259 गाड़ियों के काफिले में जम्मू से बालटाल और पहलगाम के दो बेस कैंपों के लिए रवाना हुए।

इनमें से 2510 तीर्थयात्री पारंपरिक पहलगाम रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, जबकि 2,312 ने छोटे बालटाल रास्ते को चुना है। पहले जत्थे में 3,707 पुरुष तीर्थयात्री, 816 महिला तीर्थयात्री, 16 बच्चे, 246 साधु और 37 साध्वियां शामिल हैं। काफिले में 106 बसें, 39 मध्यम मोटर वाहन, 111 हल्के मोटर वाहन और तीन दोपहिया वाहन शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बालटाल जाने वाला काफिला सुबह 6ः10 बजे भगवती नगर से निकला और उसके बाद पहलगाम जाने वाला काफिला सुबह 6ः35 बजे रवाना हुआ। दोनों काफिलों को कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में ले जाया गया।

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और परेशानी-मुक्त बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ-सफाई, रहने की जगह और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बाबा बर्फानी के तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तवी आरती और लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक जागृति की यह पवित्र यात्रा अनगिनत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने देश भर के श्रद्धालुओं को इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा लंबे समय से एक जीवंत सूत्र रही है, जो अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों को आस्था के एक साझे ताने-बाने में पिरोती है। उम्मीद है कि तीर्थयात्री दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और फिर बालटाल और नुनवान बेस कैंप जाएंगे, जहां से वे तय कार्यक्रम के अनुसार पवित्र गुफा मंदिर की आगे की यात्रा शुरू करेंगे।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की पूजा-अर्चना

जम्मू, 02 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के प्रथम दल को रवाना करने से पहले पूजा-अर्चना की । उप राज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक आस्था का एक कालातीत प्रतीक है। यह देश के सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें एक ऐसी जिम्मेदारी शामिल है जो देशभर के लाखों लोगों की श्रद्धा को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तीर्थयात्रा की पवित्रता बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षा, सम्मान, आराम और देखभाल के सर्वोत्तम मानक मिलें। सिन्हा ने कहा, ‟इस पवित्र अवसर पर मैं एक ऐसे जम्मू की कल्पना करता हूं जो आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक अध्ययन और मानवीय मूल्यों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरे। मैं तवी रिवरफ्रंट को पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और आधुनिक शहरी योजना के लिए एक मिसाल बनते देखना चाहता हूं, जहां प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक सुविधाएं एक-दूसरे के पूरक बनकर विकास का एक नया मॉडल तैयार करें।‟

उप राज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सदियों से जम्मू आध्यात्मिक जागरुकता, सांस्कृतिक समृद्धि और ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। अपने प्राचीन मंदिरों के साथ यह भूमि लंबे समय से आध्यात्मिक

चिंतन और भारतीय संस्कृति के बेहतरीन मूल्यों का प्रतीक रही है। यह देखकर खुशी होती है कि जम्मू उस खास पहचान को फिर से हासिल कर रहा है जिसके लिए इतिहास में इसकी सराहना की गई है। उन्होंने कहा, मैं शहर को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करता हूं।

उपराज्यपाल ने जम्मू की पुरानी मंडी स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में दर्शन किए

जम्मू, 2 जुलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू की पुरानी मंडी स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने सभी के सुख, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

अपनी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र वार्षिक तीर्थयात्रा पर जा रहे साधुओं और साध्वियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर महंत श्री रामेश्वर दास विधानसभा सदस्य श्री युद्धवीर सेठी और श्री कुलदीप राज दुबे धार्मिक नेता और वरिष्ठ अधिकारी उपराज्यपाल के साथ उपस्थित थे।

खबर संक्षेप

श्री अमरनाथ यात्रियों के कश्मीर पहुंचने परपारंपरिक तरीके से स्वागत

श्रीनगर, 02 जुलाई । सालाना अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 4,822 यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को काजीगुंड में नवयुग टनल के रास्ते कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ।

इस दौरान बहुत ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम किए गए और अधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया।

अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हरी झंडी दिखाने के बाद जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ काफिला कई लेवल की सुरक्षा के बीच घाटी में दाखिल हुआ।

जैसे ही यात्री श्रीनगर पहुंचे उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू और कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। स्वागत में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे पारंपरिक तरीके शामिल थे।

अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित और आसान यात्रा पक्का करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यात्रा के रास्ते पर पुलिस, पैरामिलिट्री फ़ोर्स और ट्रैफ़िक कर्मचारियों की और तैनाती की गई है।

सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल के दो रास्तों से शुरू होने वाली है और 57 दिनों तक चलेगी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना

श्रीनगर, 02 जुलाई । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यात्रा के सुचारु संचालन हेतु इस सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा प्रारंभ होने से काफी पहले ही देश भर में बैंक शाखाओं एवं ऑनलाइन माध्यम से Advance Registration की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अधिकांश श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना registration पहले ही करा लिया है।

इसीलिए तत्काल (Tatkal) registration की slots अत्यंत सीमित हैं 7 सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है की वे अपना advance registration करने के पश्चात ही जम्मू व कश्मीर आएं 7

इसीलिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में बिना registration के पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को तत्काल सुविधा के अंतर्गत adjust करना संभव नहीं है। अतः ऐसे श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अपने क्रम (Turn) की प्रतीक्षा करें तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले तिथि के अनुसार ही यात्रा करें।

यह भी देखा गया है कि अनेक registered श्रद्धालु अपने registration date से पूर्व यात्रा हेतु जम्मू और कश्मीर पहुंच रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को उसकी registration date से पहले यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया अपने registered date के अनुसार ही यात्रा के लिए आएं।

जो श्रद्धालु बिना registration के जम्मू व कश्मीर पहुचे हैं, उनसे पुनः अनुरोध है कि वे अपने क्रम की प्रतीक्षा करें।

निश्चिंत रहें, सभी श्रद्धालुओं को यात्रा करने का अवसर मिलेगा, परंतु यह निर्धारित प्रक्रिया एवं उपलब्ध क्षमता के अनुसार ही संभव होगा।

किश्तवाड़ में 5 जुलाई तक के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी, लोगों से जोखिम वाली जगहों से दूर रहने की अपील

जम्मू, 2 जुलाई। किश्तवाड़ ज़िला प्रशासन ने गुरुवार को इलाके में रविवार तक भारी बारिश, आंधी-तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों, खासकर नदी के किनारे रहने वालों से सावधान रहने और जोखिम वाली जगहों से दूर रहने की अपील की है।

किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी चेतावनी के अनुसार इलाके में आम तौर पर बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है।

कुछ इलाकों में भारी बारिश, अचानक तेज़ बौछारें और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मौजूदा मौसम की स्थिति से जोखिम वाली जगहों पर अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हो सकती हैं। चेतावनी में कहा गया है कि निवासियों, खासकर जल निकायों, धाराओं और नालों के पास रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी जगहों से दूर रहें और मौसम ठीक होने तक सभी ज़रूरी सावधानियां बरतें। ज़िला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों जैसे राजस्व, लोक निर्माण विभाग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिजली, जल शक्ति, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, एनएचआईडीसीएल और बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। चेतावनी के अनुसार, फील्ड स्टाफ को सक्रिय रहने और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सभी तहसीलदारों को भी जान-माल के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

भारत टेक्स 2026 - 14 जुलाई से दिल्ली में सजेगा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र मेला

नई दिल्ली, 02 जुलाई । भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2026 आगामी 14-17 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 20 से अधिक देश भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारत के वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल इकोसिस्टम) की व्यापकता और विविधता को एकीकृत वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। वैश्विक वस्त्र मेला भारत की वस्त्र, फैशन, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा, यह वैश्विक कपड़ा उद्योग के सभी प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देकर देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शीर्ष पर पहुंचाना है। इस मौके पर लगभग 3,500 क्यूरेटेड बी2बी बैठकें, 100 से अधिक बी2जी बैठकें तथा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, बाजार पहुँच एवं संस्थागत सहयोग से जुड़े 20 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता, एआई के क्षेत्र में करेंगे सहयोग

नई दिल्ली, 02 जुलाई। भारत और जापान गुरुवार को आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग करने को सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आज 16 बिन्दुओं पर सहमति बनी। इसमें आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र, एआई के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य और ऊर्जा लचीलापन पर संयुक्त वक्तव्य शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज अपनी समकक्ष सनाए तकाइची के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखरवार्ता में भाग लिया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तकाइची को ‘छोटी बहन’ कहकर संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान भारत-जापान संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक वार्ता हुई, जिनमें व्यापार एवं निवेश, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियां, रक्षा और जन-समुदाय आदान-प्रदान शामिल थे। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ठोस

प्रगति हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपनाया- आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणापत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य और ऊर्जा लचीलापन पर संयुक्त वक्तव्य। दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रमुख समझौता ज्ञापनों और समझौतों के आदान-प्रदान को देखा। दोनों पक्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों की सूची पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि अगले 10 सालों में भारत जापान से 10 ट्रिलियन येन (जापानी मुद्रा) के निवेश और देश में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वार्ता के बाद पत्रकार वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज की बैठकों से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो मोटे तौर पर तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र हैं आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन-समुदाय आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर विचार-विमर्श किया।

रक्षा मंत्री से मिले सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार-विमर्श

- राजनाथ सिंह ने जनरल धीरज सेठ को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 02 जुलाई । देश के 31वें सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद गुरुवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यह बैठक भारतीय सेना की संचालन संबंधी तैयारियों और सुरक्षा मामलों पर केंद्रित थी। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने जनरल धीरज सेठ को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं।

रक्षा मंत्रालय में यह शिष्टाचार भेंट ऐसे समय में हुई है, जब भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बना रहा है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सशस्त्र बलों के व्यापक आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री और नए थल सेना प्रमुख के बीच यह मुलाकात आने वाले समय में भारतीय सेना की रणनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मुलाकात के दौरान भारतीय सेना की वर्तमान परिचालन तैयारियों, सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति, सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

जनरल धीरज सेठ ने 30 जून को भारतीय थलसेना की कमान संभाली है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने बुधवार को ‘विजय’ नामक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मकसद स्वदेशी तरीकों का इस्तेमाल करके

युद्ध जीतना होगा। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के बारे में लगातार विजिलेंस बनाए रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का असरदार तरीके से मुकाबला करने के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस का हाई लेवल बनाए रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकताओं में सेना में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग, एआई-आधारित क्षमताओं का विस्तार, स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा तथा तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को और मजबूत करना शामिल है।

भारत और पाकिस्तान को बातचीत से मसले सुलझाने चाहिए : उमर अब्दुल्ला

शोपियां, 02 जुलाई । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करके आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति की वकालत करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

शोपियां में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है और यह दशकों से चला आ रहा है और पिछले साल पहलगाम की घटना के बाद यह तनाव और बढ़ गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे गए उस हालिया पत्र का भी ज़िक्र किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अपील पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर के नेताओं की ऐसी बातों पर आलोचना क्यों होती है,

जबकि वरिष्ठ आरएसएस नेताओं द्वारा बातचीत के पक्ष में दिए गए बयानों पर कोई आलोचना नहीं होती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा कि मकसद बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से पड़ोसी देशों के बीच बेहतर संबंध देखना है।

संपादकीय

यात्रा के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा भगवती नगर यात्री निवास से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों के लिए रवाना किए जाने के साथ ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का एक नया स्तर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह मजबूत और व्यापक दिखाई दे रहा है। सड़कें हों, बाजार, सरकारी कार्यालय, बैंक, एटीएम या अन्य सार्वजनिक स्थान–हर जगह सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने आम लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास और भरोसा बढ़ाया है। इस प्रभावी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 670 से अधिक कंपनियां तैनात की हैं, जो अमरनाथ यात्रा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी अर्धसैनिक तैनाती है। इसके अलावा सेना और जम्मू–कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरी सतर्कता के साथ तैनात हैं, ताकि 28 अगस्त को संपन्न होने वाली इस यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जम्मू–कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पूरे यात्रा मार्ग को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली के तहत रखा गया है।

सुरक्षा व्यवस्था हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होती है, क्योंकि राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा यात्रा को बाधित करने या शांति भंग करने की कोशिशों से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह सराहनीय है कि पिछले कई वर्षों में सरकार ने सुरक्षा से जुड़े अनेक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू की हैं, जिन्होंने यात्रा को बाधित करने के प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस वर्ष सरकार ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने श्रद्धालुओं और यात्रा से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम उठाए हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आम जनता के सहयोग से इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होगी। इसे सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से श्रद्धालुओं का भी दायित्व है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि यह पवित्र यात्रा सभी के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अविस्मरणीय बन सके।

यह आवश्यक है कि संबंधित सभी पक्ष अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें, ताकि वर्ष 2026 की श्री अमरनाथ यात्रा न केवल पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे, बल्कि एकता, आस्था, बेहतर समन्वय, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव का नया उदाहरण भी प्रस्तुत करे।

होर्मुज संकट का मुकाबला– भारत ने सबसे बड़े ऊर्जा संकट का कैसे सामना किया

हालांकि, आपूर्ति प्रयास का केवल आधा हिस्सा था, क्योंकि मांग को भी प्राथमिकता देना जरूरी था। घरों में जाने वाला रसोई गैस पूरा सुरक्षित रखा गया और इस कीमती आपूर्ति को काले बाज़ारियों से बचाने के लिए डिजिटल सत्यापन कोड अनिवार्य किया गया। हर नागरिक को उनके ज़रूरत के समय सिलेंडर मिलें, लेकिन कोई भी सिलेंडर जमा न कर सके, इसके लिए 25 दिन और 45 दिन की सीमा लगाई गई।

– हरदीप सिंह पुरी

जब फरवरी के अंत में होर्मुज की खाड़ी बंद हुई, तो भारत सरकार ने एक प्राथमिकता का चयन किया– हमारे देश के नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर समुदायों, को अभूतपूर्व आपूर्ति और मूल्य व्यवधानों से सुरक्षित रखना। इस प्राथमिकता के आस–पास ही अन्य प्रयास किये जाने थे। यह भावना खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की थीऔर यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा व्यवधान के लगभग चार महीनों तक बनी रही।

तथ्यों के पता चलने से पहले ही भारत को लेकर निर्णय किये जा रहे थे- तर्क यह था कि एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, होर्मुज के बंद होने से संभल नहीं पायेगा, जिससे होकर दुनिया का20–30% से अधिक हाइड्रोकार्बन गुजरता है। पेट्रोल पंप में कुछ ही दिनों में तेल ख़त्म हो जाएगा, कीमतें आसमान छुएंगी (जैसे कि कई अन्य देशों में हुआ) और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज स्टॉक भरे हुए हैं, पंप खुले हैं, और भारतीय उपभोक्ता ने इस संकट के दौरान ऊर्जा के लिए दुनिया के किसी भी अन्य उपभोक्ता की तुलना में कम भुगतान किया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसे कैसे किया गयाऔर इससे गलत आख्यानों को जवाब भी मिल जाएगा।

28 फरवरी को ईरान पर हमलों से वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण मार्ग–खंड बंद हो गया और एलपीजी आपूर्ति ने भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की, क्योंकि दुनिया में केवल अमेरिका और मध्य पूर्व ही प्रमुख एलपीजीनिर्यातक हैं। भारत की लगभग 60% एलपीजीपहले मध्य पूर्व से आती थीऔर यह आपूर्ति तुरंत लगभग शून्य हो गई। फिर आपूर्ति और मांग, दोनों को लेकर एक युद्धकक्ष ऑपरेशन शुरू हुआ, हर कार्गो, हर रिफाइनरी, हर बॉटलिंग प्लांट की निगरानी की गयी, ताकि पूरे देश के सभी रसोईघरों में खाना पकाने के लिए आग जलती रहे।

आपूर्ति के संबंध में, 8 मार्च को एलपीजी नियंत्रण आदेश पारित किया गया, जिसके तहत सभी रिफाइनरियों को अपना एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के लिए सभी सी3–सी4 कार्बन स्ट्रीम को बदलने का निर्देश दिया गया। जो रिफाइनरी कभी कुकिंग गैस नहीं बनाती थीं, बदलाव किया गया और उत्पादन 35टीएमटीप्रति दिन से बढ़कर 54 टीएमटी प्रति दिन हो गया। युद्ध की सर्वाधिक विभीषिका के दौरान, जब होर्मुज से कोई भी जहाज बाहर नहीं निकल रहा था, तब 12 से अधिक भारतीय एलपीजी जहाजें चुपचाप होर्मुज से बिना कोई टोल दिए निकाल दी गईं – किसी भी देश के लिए यह सबसे बड़ी संख्या थी। कार्गो सुरक्षित किए गए तथा यानबू और फुजैरा बंदरगाहों से लाल सागर रास्ते के जरिए कार्गो जहाज–से–जहाज स्थानांतरित किये गये। अमेरिका से कार्गो को सुरक्षित करने की स्थिति में भी खाली जहाज भेजे गए, नए माल लेने के लिए जहाज हॉर्मुज के अंदर भेजे गए तथा अल्जीरिया, जापान और कनाडा जैसे कई देशों के साथ नई आपूर्ति व्यवस्था शुरू की गयी। मैंने हर उस देश के ऊर्जा मंत्री से कई बार बात की, जो एलपीजी निर्यात कर सकता था। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि खाड़ी क्षेत्र के अंदर या बाहर का हर उत्पादक, जिसके साथ हमने व्यापार किया, हमारे साथ खड़ा रहा।

हालांकि, आपूर्ति प्रयास का केवल आधा हिस्सा था, क्योंकि मांग को भी प्राथमिकता देना जरूरी था। घरों में जाने वाला रसोई गैस पूरा सुरक्षित रखा गया और इस कीमती आपूर्ति को काले बाज़ारियों से बचाने के लिए डिजिटल सत्यापन कोड अनिवार्य किया गया। हर नागरिक को उनके ज़रूरत के समय सिलेंडर मिलें, लेकिन कोई भी सिलेंडर जमा न कर सके, इसके लिए 25 दिन और 45 दिन की सीमा लगाई गई। चूँकि, वाणिज्यिक सिलेंडरों को नियंत्रित नहीं किया जाता और कोई भी खरीदार उपलब्ध पूरी आपूर्ति एक साथ खरीद सकता था, इसलिए इन्हें उद्योग संघों और राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से भेजा गया, ताकि हर किसी को पर्याप्त मिले और कोई भी जमा न कर सके। उद्योग को पाइप प्राकृतिक गैस अपनाने के लिए कहा गया, बड़े रसोईघरों और प्रतिष्ठानों को अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहाँ संभव था और घरेलू पाइप गैस और सीएनजी को बिना कटौती वाले वर्ग में रखा गया।सरकार के सभी विभागों ने मिलकर नगर निगम की शीघ्र मंजूरी के ज़रिए पाइप गैस कनेक्शनों की ओर बदलाव को संभव बनाया। कई उपभोक्ता, जिनमें प्रवासी भी शामिल थे, एजेंट से सिलेंडर खरीदते थे, जो अब डीएसी की शर्तों के कारण सिलेंडर नहीं ला पा रहे थे, इसलिए पूरे देश में 5 किलो का मुफ्त व्यापार सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, जब तक इसका इस्तेमाल लगभग दोगुना नहीं हो गया। लोगों में भय पैदा करने वाले और खराब स्थिति बताने वाले झूठी अफवाहें फैलाने लगे और झूठे वीडियो शेयर करने लगे ताकि कमी, घबराहट और अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके, जबकि सरकार हर दिन युद्धकक्ष मोड में कई क्रांतिकारी कदम उठा रही थी, ताकि देश में किसी भी जगह आपूर्ति में बाधा न आये।

इस सब के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ संकल्प था – भारतीय नागरिक को सुरक्षा दी जायेगी चाहे खजाने पर कितना भी बोझ क्यों न पड़े —रूस–यूक्रेन संघर्ष और जीवन को संकट में डालने वाली कोविड चुनौती से पैदा हुए ऊर्जा संकट के दौरान यही ‘भारत की राह’ रही है। फरवरी और जून के बीच, रसोई गैस के अंतरराष्ट्रीय मानक, सऊदी सी पी, में लगभग 50% की वृद्धि हुई, और फिर भी, उस आयातदर पर 1,600 से अधिक की कीमत वाला सिलेन्डर उज्ज्वला घर तक 642 में पहुँचा। मोदी सरकार हर उज्ज्वला सिलेंडर पर लगभग 900 का और हर अन्य घर के लिए जाने वाले सिलेंडर पर करीब ?600 का नुकसान उठाती है, आज सभी भारतीय परिवार अपने रसोई गैस के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, स्पेन या फ्रांस के घरों की तुलना में बहुत कम भुगतान कर रहे हैं।

मार्च में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 प्रति लीटर की कटौती का साहसिक निर्णय लिया गया, जिससे कीमत–वृद्धि में कमी आयी, जबकि कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गयी थी और सरकारी तेल कंपनियों ने इस तिमाही में हर दिन 500 से 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाया। इसी अवधि में, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 40% से अधिक और ब्रिटेन में करीब 20% बढ़ी, जबकि यूरोप के बड़े हिस्से में भी दहाई अंक की वृद्धि हुई, लेकिन भारत में कीमत में लगभग 7% की ही वृद्धि हुई।

एक और कहानी यह थी कि पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, विदेशी भंडार ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आर्थिक संभावनाएँ धुंधली हो जाएंगी। भंडार खुद जवाब देते हैं, जो लगभग 690 बिलियन डॉलर के करीब है। यह संघर्ष शुरू होने के सप्ताह में रिकॉर्ड किये गये उच्चतम दर से केवल थोडा कम है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है।

यह कहा गया कि भारत के पास केवल 8 या 9 दिन का भंडार है और उसके पास ज्यादा भंडार रखने की वास्तविक क्षमता नहीं है, यह दावा 1.5 बिलियन लोगों वाली बड़ी ऊर्जा अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को गलत रूप में समझता है। आप किसी देश को कुछ गुफाओं से नहीं चला सकते, क्योंकि जमीन के भीतर रखी गई ऊर्जा से कुछ भी कमाई नहीं होती और उसे रखने में बहुत ज्यादा खर्च भी आता है। इसके बजाय आप इसे इम्पोर्ट टर्मिनल, डिपो, पाइपलाइन, रिफाइनरी और पूरे देश में फैले स्टोरेज के सिस्टम के जरिए चलाते हैं, और आज भारत के पास 24 रिफाइनरी हैं, 47,000 किलोमीटर से ज्यादा तेल और गैस की पाइपलाइनें हैं, और 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जो प्रतिदिन करीब 8 करोड़ लोगों की सेवा करते हैं।

उस प्रणाली की वास्तविकता की जांच, महाप्रलय का भय दिखाने वाले किसी भविष्यवक्ता की स्लाइड पर दिखाए गए आंकड़े से नहीं होती। असली जांच है – आधुनिक समय के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के लगभग चार महीने गुजर जाने के बाद, क्या देश को अपने लोगों पर राशनिंग लागू करनी पड़ी, क्या ईंधन सिर्फ सम–विषम नंबर प्लेट्स के हिसाब से देना पड़ा, क्या घर में ऑफिस बनाना पड़ा या क्या हर दिन 5 बजे अपने पंप बंद करने पड़े। भारत को इनमें से कोई काम नहीं करना पड़ा। यह सब इसलिए संभव हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों में इसकी तैयारी की गई थी। हमारे कच्चे तेल के बास्केट को 27 देशों से बढ़ाकर 41 करना, हमारे आयात टर्मिनल को दुगना करना, और प्रधानमंत्री मोदी के तहत एक दशक में बनाए गए पाइपलाइन और भंडार, होर्मुज के बंद होने पर ये सभी चीजें उपयोगी साबित हुईं; यही वजह थी कि रोशनी जलती रही।

इस स्तर का संकट एक देश को उसकी असली क्षमता दिखाता है। भारत ने होर्मुज के बंद होने की बाधा पार की और देश में कहीं भी बिना किसी कमी के आपूर्ति जारी रही। इस अनुभव से सीख लेकर, हम अपनी ऊर्जा सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण करेंगे, लेकिन जब इस संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, तो एक पंक्ति मौजूद रहनी चाहिए- मानव स्मृति का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हमारे तटों तक पहुंचा, लेकिन 150 करोड़ भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे।

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।)

जब शहर तपते हैं

– डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत आज तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन– दो ऐसी प्रक्रियाओं के संगम पर खड़ा है जो देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। एक ओर शहर विकास, रोजगार और नवाचार के केंद्र हैं तो दूसरी ओर वे बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, शहरी बाढ़, जल संकट, वायु प्रदूषण और चरम मौसमी घटनाओं के सबसे बड़े शिकार भी बनते जा रहे हैं। सामान्यतः जलवायु परिवर्तन को पर्यावरणीय समस्या माना जाता है किंतु भारतीय शहरों का अनुभव बताता है कि यह केवल प्रकृति का संकट नहीं है; यह शहरी शासन, सामाजिक न्याय और विकास मॉडल की सीमाओं को उजागर करने वाला बहुआयामी संकट है।

इस संकट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो शहरों की अर्थव्यवस्था और जीवन–प्रणाली को प्रतिदिन संचालित करते हैं लेकिन नीतियों और योजनाओं में सबसे पीछे रह जाते हैं। इनमें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी मजदूर, सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले और स्वच्छता कार्यकर्ता प्रमुख हैं। विडंबना यह है कि जिन लोगों के श्रम से शहर चलते हैं, वही लोग जलवायु परिवर्तन के सबसे असुरक्षित शिकार बनते हैं।

भारत की लगभग 35 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और आने वाले दशकों में यह अनुपात तेजी से बढ़ेगा। शहरों का विस्तार अक्सर बिना समुचित योजना के हुआ है। हरित क्षेत्रों का सिकुड़ना, जल निकायों का अतिक्रमण, अनियंत्रित कंक्रीटीकरण और कमजोर जल निकासी व्यवस्था ने शहरों की प्राकृतिक जलवायु सहनशीलता को कम कर दिया है। परिणामस्वरूप थोड़ी–सी अधिक वर्षा भी व्यापक जलभराव और बाढ़ का कारण बन जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पर गंभीर जल संकट उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते तापमान ने शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को और तीव्र बना दिया है, जिससे शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो जाते हैं।

यह स्थिति केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं है। यह शहरी शासन की कमियों को भी दर्शाती है। अनेक नगर निकायों के पास न तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और न ही जलवायु परिवर्तन के अनुरूप दीर्घकालिक योजना बनाने की क्षमता। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, डेटा आधारित निर्णयों की कमी और अल्पकालिक विकास परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता ने समस्या को और जटिल बना दिया है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को अब 卐क्लाइमेट जस्टिस卐 अर्थात जलवायु न्याय के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जिन लोगों का कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है, वही इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विभिन्न आकलनों के अनुसार शहरों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हैं। उनके पास स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसी सुविधाएँ नहीं होतीं। उनकी आय प्रतिदिन के कार्य पर निर्भर करती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन उनके लिए केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आजीविका का संकट बन जाता है।

जब भीषण गर्मी पड़ती है, निर्माण कार्य धीमे हो जाते हैं, सड़क विक्रेताओं की बिक्री घट जाती है, रिक्शा और ई–रिक्शा चालक कम समय तक काम कर पाते हैं तथा दिहाड़ी मजदूरों की आय प्रभावित होती है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ से बाजार बंद हो जाते हैं, परिवहन बाधित होता है और लाखों लोगों की रोज़ी–रोटी ठप पड़ जाती है। अधिकांश अनौपचारिक श्रमिकों के पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होता। परिणामस्वरूप वे कर्ज, भूख और आर्थिक असुरक्षा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।

शहरों की झुग्गी बस्तियाँ जलवायु संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं। अधिकांश झुग्गियाँ नदी किनारे, नालों के आसपास या निम्न–स्तरीय भूमि पर स्थित होती हैं, जहाँ बाढ़ और जलभराव का खतरा अधिक रहता है। इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। भारी वर्षा के बाद दूषित जल फैलने से डेंगू, मलेरिया, हैजा और अन्य जलजनित रोग तेजी से फैलते हैं। गर्मी के दौरान टिन की छतों वाले छोटे घर असहनीय तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

स्वच्छता कार्यकर्ताओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। वे प्रतिदिन कचरा संग्रह, नालों की सफाई, सीवर प्रबंधन और अपशिष्ट निस्तारण जैसे कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी, दूषित जल और चरम वर्षा जैसी परिस्थितियाँ उनके कार्य को और अधिक जोखिमपूर्ण बना रही हैं। अनेक स्थानों पर आज भी पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। हीट स्ट्रेस, संक्रमण, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी बीमारियाँ और जहरीली गैसों का खतरा लगातार बना रहता है। विडंबना यह है कि शहरों की स्वच्छता बनाए रखने वाले ये कर्मचारी स्वयं सुरक्षित कार्य परिस्थितियों से वंचित हैं।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद समय–समय पर सीवरों में दम घुटने से होने वाली मौतें यह दर्शाती हैं कि कानून और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा के समय सीवरों और नालों की सफाई का दबाव बढ़ जाता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।

महिलाएँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अलग प्रकार से झेलती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेती हैं। जल संकट बढ़ने पर पानी लाने का अतिरिक्त बोझ अक्सर महिलाओं पर ही पड़ता है। बाढ़ या गर्मी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी अधिक बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का अतिरिक्त भार भी महिलाओं को ही उठाना पड़ता है।

प्रवासी श्रमिक जलवायु संकट के सबसे अदृश्य पीड़ितों में हैं। वे प्रायः अस्थायी आवासों में रहते हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। अत्यधिक गर्मी, वर्षा या बाढ़ के समय उनके पास सुरक्षित आश्रय नहीं होता। रोजगार रुकने पर वे आय और भोजन दोनों के संकट से जूझते हैं। महामारी के दौरान यह स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आई थी और जलवायु परिवर्तन भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को और गंभीर बना सकता है।

शहरी शासन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन को अक्सर केवल पर्यावरण विभाग या वन विभाग का विषय मान लिया जाता है, जबकि इसका संबंध स्वास्थ्य, परिवहन, आवास, रोजगार, जल प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित लगभग सभी क्षेत्रों से है। यदि नगर नियोजन में जलवायु जोखिमों को शामिल नहीं किया जाएगा तो भविष्य की समस्याएँ और गंभीर होंगी। आज आवश्यकता ऐसे शहरों की है जो केवल स्मार्ट न हों बल्कि जलवायु–सहिष्णु और सामाजिक रूप से समावेशी भी हों। इसके लिए हरित अवसंरचना का विस्तार, वर्षा जल संचयन, शहरी जल निकायों का संरक्षण, हरित पट्टियों का विकास, छायादार सार्वजनिक स्थान, प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक जल निकासी प्रणाली विकसित करनी होगी। साथ ही प्रत्येक शहर के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हीट एक्शन प्लान और बाढ़ प्रबंधन रणनीति तैयार करनी होगी।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

खेल कूटनीति– बास्केटबॉल से अमेरिका–भारत निकटता

चार्वी अरोड़ा, स्पैन पत्रिका

भारत के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ियों की एक पीढ़ी के लिए अमेरिका नक्शे पर भले ही दूर हो पर उन्हें वह कहीं करीब महसूस होता है। वे सोशल मीडिया पर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के मशहूर खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर उनके खेल की बारीकियों का अध्ययन करते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर चर्चा करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखते हैं।

मई 2026 में यह जुड़ाव नई दिल्ली स्थित अमेरिकन सेंटर में आयोजित फ्रीडम 250 स्लैम डंक एक्सपीरियंस के दौरान साकार हुआ। दिल्ली के स्कूलों और बास्केटबॉल अकादमियों से आए 150 से अधिक विद्यार्थी एनबीए के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए एकत्र हुए। एनबीए अमेरिका की प्रमुख पेशेवर बास्केटबॉल लीग है और खेल के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ियों का ठिकाना है।

यह कार्यक्रम फ्रीडम 250 समारोहों के तहत आयोजित किया गया था, जो अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक पहल है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल टीम सैक्रामेंटो किंग्स के साथ साझेदारी कर विद्यार्थियों को बास्केटबॉल खेल, इस खेल में कुशल बनने और साझा आकांक्षाओं के माध्यम से जुड़ने का अवसर प्रदान किया।

भारत में बास्केटबॉल की बढ़ती पहचान

जब विद्यार्थियों से उनके बास्केटबॉल नायकों के बारे में पूछा जाता है तो वे तुरंत जवाब देते हैं- स्टीफन करी, कोबी ब्रायंट, एलन आइवरसन, डेविन बुकर और जियानिस एंटेटोकाउनम्पो। ये नाम अलग–अलग युगों, टीमों और खेलने की शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बास्केटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

कार्यक्रम के प्रतिभागियों में से एक अफ्युपांग मिश्रा के लिए एंटेटोकाउनम्पो प्रेरणा के स्रोत हैं। मिश्रा मिल्वॉकी बक्स के इस स्टार खिलाड़ी की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली हैं। कार्यक्रम में शामिल कई युवा खिलाड़ियों की तरह वह भी भारत के बाहर पेशेवर स्तर पर खेलने और अंततः खेल के सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की आशा रखते हैं।

ऐसी महत्वाकांक्षाएं पूरे दिन कार्यक्रम के दौरान एक साझा विषय बनी रहीं। नेहरू वर्ल्ड स्कूल के 16 वर्षीय खिलाड़ी कृष्णा सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, एक दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं। वह कहते हैं, मेरा लक्ष्य एनबीए तक पहुंचना है। उनके सहपाठी मयंक त्यागी का लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है। वह कहते हैं, मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने शूटिंग, पासिंग और ड्रिब्लिंग स्टेशनों पर अभ्यास किया और सैक्रामेंटो किंग्स के कोच तथा दिल्ली के अन्य खिलाड़ियों से बातचीत की। कई विद्यार्थियों के लिए इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और मज़बूत किया कि भारत में बास्केटबॉल का भविष्य उवल है।

नेहरू वर्ल्ड स्कूल की रुद्राक्षी वर्मा कहती हैं,भारत में बास्केटबॉल बढ़ रहा है और इसका वास्तव में भविष्य है। उनका मानना है कि यह खेल ऐसे सबक सिखाता है जो खेल प्रदर्शन से कहीं आगे हैं। वह कहती हैं, यह सिर्फ खेल के बारे में नहीं है। हमें इससे नए लोगों से मिलने–जुलने का अवसर मिलता है, नई तरह की चीजें सीखने को मिलती हैं, हम खेल भावना सीख पाते हैं, जो हम किताबों या किसी अकादमिक शिक्षा से नहीं सीख सकते।

शिव नादर स्कूल की सिमरन एनबीए के महान खिलाड़ी कोबी ब्रायंट से प्रेरणा लेती हैं, जिनकी समर्पण भावना और अनुशासन आज भी दुनिया भर के खिलाड़ियों को प्रभावित करते हैं। ब्रायंट की प्रसिद्ध माम्बा मेंटैलिटी–एक ऐसा दर्शन जो निरंतर आत्म–सुधार और दृढ़ता पर आधारित है– उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

एनबीए दिग्गज से प्रशिक्षण

विद्यार्थियों ने एनबीए दिग्गज हॉल ऑफ फेमर व्लाडे डीवॉत्स की बातें भी सुनीं, जिनके लॉस एंजिलिस लेकर्स, शार्लट हॉर्नेट्स और सैक्रामेंटो किंग्स के साथ कॅरियर ने उन्हें बास्केटबॉल के सबसे प्रसिद्ध पहचान वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक बनाने में मदद की। प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए डीवॉत्स ने जोर दिया कि सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि कोई व्यक्ति कहां से शुरुआत करता है। अपने जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ है। आप अपने सपनों को किसी भी तरह हासिल कर सकते हैं लेकिन आपको सही काम करने होंगे। डीवॉत्स ने खेल और अकादमिक शिक्षा के बीच संतुलन के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा, यदि आप खेल से प्यार करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बास्केटबॉल निश्चित रूप से आपको एनबीए खिलाड़ी बनने का रास्ता देता स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए संदेश स्पष्ट था– प्रतिभा महत्वपूर्ण है लेकिन प्रतिबद्धता और तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। डीवात्स ने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि जो लोग अपने विकास में निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए अवसर अप्रत्याशित स्थानों से भी उभर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप खेल से प्यार करते हैं, अपने खेल पर मेहनत करते हैं और अपने खेल को विकसित करते हैं तो आगे चलकर, कौन जानता है, आप एनबीए तक पहुंच सकते हैं अमेरिका–भारत खेल कूटनीति का जीवंत उदाहरण बास्केटबॉल कौशल से आगे बढ़कर इस कार्यक्रम ने सार्थक संवाद के अवसर भी प्रदान किए। कई विद्यार्थियों ने कहा कि अमेरिकी प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत ने उन्हें खेल से जुड़े लोगों और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने का अवसर दिया। विद्यार्थी प्रतिभागी थियो ने कहा कि कार्यक्रम की सबसे खास बात इसकी आपसी संवाद की प्रकृति थी। वह कहती हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अलग–थलग महसूस न करे। यह बहुत समग्र अनुभव था। रुद्राक्षी के लिए इस अनुभव ने भारत और अमेरिका के युवाओं के बीच समानताओं को उजागर किया। वह कहती हैं, हमें यह जानने का मौका मिलता है कि वे क्या सोचते हैं, वे कैसे हैं, खेल के प्रति उनकी मानसिकता क्या है और हमारी समानताएं क्या हैं। बास्केटबॉल प्रशिक्षक और कंटेंट क्रिएटर देवांश पावडीघड़ा ने इन संबंधों को स्वयं अनुभव किया है। अमेरिका में अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अब भारत में युवा प्रतिभाओं को विकसित करने के साथ–साथ देश की बढ़ती बास्केटबॉल संस्कृति का दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं। वह कहते हैं, खेल, कला और संगीत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी सीमाओं को पार कर जाती हैं। पावडीघड़ा का मानना है कि बास्केटबॉल लोगों में एकता की भावना पैदा करता है, जैसा बहुत कम मंच कर पाते हैं। इस खेल के माध्यम से बने उनके संबंध आज भी उनके जीवन और कॅरियर को आकार दे रहे हैं। वह कहते हैं, दोस्त बनाने, नए लोगों से मिलने और आत्मविश्वास विकसित करने में बास्केटबॉल ने मेरी बहुत मदद की है। यह लोगों को अनोखे तरीके से जोड़ता है और यही इसकी सबसे अद्भुत बात है।

उपराज्यपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लिया भाग

जम्मू, 2 जुलाई (हि.स.) उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज भारती एयरटेल फाउंडेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (जम्मू कश्मीर) और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम इन तीनों संस्थाओं द्वारा मिलकर तैयार किए गए शिक्षण संसाधनों को लॉन्च करने का एक औपचारिक मंच था। इसका मकसद शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करना और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था।इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल एक सामूहिक संकल्प है और यह इस बुनियादी सच्चाई पर आधारित है कि जब हम शिक्षकों को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने छात्रों में आत्मविश्वास जगाते हैं। जब शिक्षक सशक्त होते हैं तो छात्रों में आत्मविश्वास आता है। जब स्कूल मजबूत होते हैं तो समाज अधिक लचीला बनता है और जब शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ती है तो जम्मू-कश्मीर और देश एक उज्जवल, सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ते हैं।

हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बदलाव लाना है। जब सीखना असल ज़िंदगी के अनुभवों से जुड़ता है तो यह पीढ़ीगत बदलाव लाता है। शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत परीक्षा के नतीजों में नहीं बल्कि जीवन बदलने की उसकी क्षमता में है। एक समर्पित शिक्षक किस्मत संवारता है। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के स्कूल इस पहलू पर ध्यान दें और जीवन-निर्माण की प्रयोगशालाएं बनें । यह एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम व्यापक नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान से भी जुड़ा है। इसका मकसद शिक्षण विधियों में सुधार करना और छात्रों को आज के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से बचाना है। उपराज्यपाल ने कहा कि नशीली दवाओं के सेवन, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, डिजिटल दुनिया के खतरों और बदलती जीवनशैली के बढ़ते चलन ने स्कूल की भूमिका को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोपियां के विकास कार्यों की समीक्षा की, जिले को 76 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

****शोपियां, 02 जुलाई।** मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शोपियां जिले के विकास कार्यों, प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनसेवाओं की स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जिले के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं समान विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने शोपियां के लोगों को 76.45 करोड़ रुपये** की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया तथा किसानों, सेब उत्पादकों और विभिन्न जनप्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना।

समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण तथा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू, कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले (शोपियां) तथा शौकत हुसैन गनई (जैनापोरा) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, उपायुक्त शोपियां, विभिन्न विभागों के प्रमुख, जिला अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बैठक में आधारभूत ढांचे के विकास में तेजी लाने, आवश्यक जनसेवाओं को मजबूत बनाने तथा चल रही विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि उनका लाभ शीघ्र लोगों तक पहुंच सके।

उपायुक्त शोपियां ने जिले की विकास स्थिति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, विभिन्न विभागों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों तथा चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त एवं उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन सराहनीय कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि शोपियां भले ही भौगोलिक दृष्टि से छोटा जिला है, लेकिन यह अपनी विश्व प्रसिद्ध सेब उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक मुगल रोड के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए लक्षित निवेश और निरंतर विकास कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों का जिले के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, वित्तीय सीमाओं के बावजूद शोपियां या जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी कमियां हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए तथा विधायकों द्वारा उठाई गई विकास संबंधी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निर्धारित समय-सीमा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने जिले में हो रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना की तथा भरोसा दिलाया कि जनता की सभी वास्तविक समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा।

डीपीएल महिला नीलामी में पारुनिका सिसोदिया बनीं सबसे महंगी खिलाड़ी

नई दिल्ली, 02 जुलाई । दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी-20 के तीसरे सीजन के लिए बुधवार को महिला खिलाड़ियों की नीलामी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पिछले दो सफल संस्करणों के बाद महिला प्रतियोगिता अब देश के सबसे रोमांचक घरेलू क्रिकेट मंचों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। नीलामी में चारों फ्रेंचाइजियों ने दिल्ली की शीर्ष महिला क्रिकेटरों और उभरती प्रतिभाओं को अपनी टीम में शामिल करने के लिए खुलकर बोली लगाई।

डीपीएल 2026 महिला नीलामी में कई खिलाड़ियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड का भी रणनीतिक उपयोग किया गया, जबकि कई बड़े नामों पर भारी रकम खर्च की गई। अंतरराष्ट्रीय अनुभव, घरेलू क्रिकेट और युवा प्रतिभाओं के बेहतरीन मिश्रण के साथ सभी चार फ्रेंचाइजियों ने संतुलित और मजबूत टीम तैयार की।

मार्की खिलाड़ियों पर रही सबसे ज्यादा नजर

मार्की खिलाड़ियों की सूची में शामिल क्रिकेटरों पर सभी टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पारुनिका सिसोदिया और सिमरन दिल बहादुर को टीम में शामिल किया। सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने सोनी यादव का साथ देने के लिए अरुषि गोयल को खरीदा। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अपनी गेंदबाजी मजबूत करने के लिए प्रिया मिश्रा को शामिल किया, जबकि आयुषी सोनी पहले से टीम में बरकरार थीं। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ ने भारतीय बल्लेबाज प्रिया पुनिया को खरीदा, जो पहले से बरकरार भारत अंडर-19 स्टार श्वेता सहरावत के साथ टीम की ताकत बढ़ाएंगी।

पारुनिका बनीं सबसे महंगी खिलाड़ी

बाएं हाथ की स्पिनर पारुनिका सिसोदिया नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। उन्हें ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 14 लाख रुपये में खरीदा। वहीं ऑलराउंडर अरुषि गोयल को सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने 11 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

जम्मू ग्रामीण पुलिस ने हाई-वैल्यू चोरी के मामले का किया खुलासा

जम्मू,, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने थाना दोमाना में दर्ज एक हाई-वैल्यू चोरी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7.82 लाख नकद, करीब 35 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी का एक जोड़ा कड़ा बरामद किया है, जबकि आरोपी के बैंक खाते में जमा 3.39 लाख की राशि भी फ्रीज कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, 24 मई 2026 को शिकायतकर्ता साहिल कुमार शर्मा अपने परिवार के साथ आनंद नगर, बोहरी स्थित बिश्मी मार्ट गए थे जहां उनकी गाड़ी से नकदी और सोने-चांदी के आभूषणों से भरा महिलाओं का हैंडबैग चोरी हो गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी शशि पॉल को गिरफ्तार किया गया।

विंबलडन - जोकोविच ने सितसिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में बनाई जगह

लंदन, 02 जुलाई (हि.स.)। सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने बुधवार को विंबलडन 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे दौर में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। सेंटर कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में 39 वर्षीय सर्बियाई दिग्गज ने शुरू से अंत तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। लगभग दो घंटे तक चले इस मुकाबले में जोकोविच ने अनुभव और सटीक खेल का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे सेट के आठवें गेम में सितसिपास के पास ब्रेक प्वाइंट बचाने का शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने लगातार दो आसान स्मैश बाहर मार दिए। जोकोविच ने इस गलती का पूरा फायदा उठाते हुए सर्विस ब्रेक किया और इसके बाद सितसिपास की वापसी की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई।

इस जीत के साथ जोकोविच ने सितसिपास के खिलाफ लगातार 12वीं जीत दर्ज की।अब तीसरे दौर में उनका मुकाबला 25वीं वरीयता प्राप्त फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच से होगा। जोकोविच आठवां विंबलडन खिताब और रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने की दौड़ में बने हुए हैं। जीत के बाद जोकोविच ने कहा,फ्रजब आप इस तरह का टेनिस खेलते हैं तो कोर्ट पर बेहद खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर खेलना हमेशा मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इन पलों को कभी हल्के में नहीं लेता। उन्होंने आगे कहा, उम्र सिर्फ एक संख्या है। 30 वर्ष से अधिक की उम्र में भी इस कोर्ट पर उतरना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

☞ यात्रीगण कृपया ध्यान दें ☜

महत्वपूर्ण सूचना

विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन अवधि में विस्तार

समस्त रेल यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये मौजूदा ठहरावों, समय, रेलमार्गों, चलने के दिनों, आदि पर निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन को जारी रखने/विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	आवृत्ति	पूर्व अधिसूचित	विस्तारित अवधि	कुल अतिरिक्त फेरे	स्थान
09425 साबरमती बीजी – हरिद्वार जं. स्पेशल	सोमवार	29.06.26	06.07.26 से 27.07.26	08	सामान्य
09426 हरिद्वार जं. – साबरमती बीजी स्पेशल	मंगलवार	30.06.26	07.07.26 से 28.07.26		
01705 जबलपुर – अयोध्या धाम जं. स्पेशल	मंगलवार	21.07.26	29.12.26 तक	24	प्रथम वाता., 2 टियर वाता., 3 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य
01706 अयोध्या धाम जं. – जबलपुर स्पेशल	बुधवार	22.07.26	30.12.26 तक	24	
04123 प्रयागराज जं. – ह. निज़ामुद्दीन जं. स्पेशल	रविवार एवं बुधवार	28.06.26	05.07.26 से 29.07.26	08	प्रथम वाता., 3 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य
04124 ह. निज़ामुद्दीन जं. – प्रयागराज जं. स्पेशल	सोमवार एवं वीरवार	29.06.26	06.07.26 से 30.07.26	08	
09639 मदार जं. – रोहतक जं. एक्सप्रेस स्पेशल	प्रतिदिन	30.06.26	03.07.26 से 15.07.26	13	सामान्य
09640 रोहतक जं. – मदार जं. एक्सप्रेस स्पेशल	प्रतिदिन	30.06.26	03.07.26 से 15.07.26	13	
04688 बडगाम - श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल	रविवार को छोड़कर	02.07.26	03.07.26 से 02.11.26	104	सामान्य
04687 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – बडगाम स्पेशल	रविवार को छोड़कर	02.07.26	03.07.26 से 02.11.26	104	

नोटः- श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान लागू यातायात विनियमन उपायों के कारण यह ट्रेन दिनांक 31.08.2026 तक बनिहाल स्टेशन पर आंशिक निरस्त रहेगी।

सर्व संबंधित को पुनः सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ी की समय-सारणी में नीचे प्रदर्शित स्टेशनों पर निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

रेलगाड़ी संख्या 09426 हरिद्वार जं. – साबरमती बीजी स्पेशल की समय-सारणी में गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली जं., गाज़ियाबाद, मेरठ सिटी एवं मुज़फ़्फ़रनगर रेलवे स्टेशनों पर परिवर्तन

स्टेशन	09426 हरिद्वार जं. – साबरमती बीजी स्पेशल			
	वर्तमान समय		परिवर्तित समय	
	आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
गुड़गांव	05:03	05:05	**04:44**	**04:46**
दिल्ली कैंट	04:43	04:45	**04:26**	**04:28**
दिल्ली जं.	04:00	04:10	**03:45**	**04:00**
गाज़ियाबाद	03:05	03:07	**02:28**	**02:30**
मेरठ सिटी	01:08	01:10	**00:38**	**00:40**
मुज़फ़्फ़रनगर	00:24	00:26	**23:43**	**23:45**

अधिसूचित अन्य जानकारी मान्य होगी।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी के लिये रेलमदद हेल्पलाइन सं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा भारतीय रेल की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें।

रेलमदद वेबसाइट देखें:- www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे आपकी सुविधा – हमारा ध्येय हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें 2270/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B)
DIVISION REASI
NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No.23 of 2026-27 Dated 01-07-2026
(Single Cover System)

For and on behalf of the Lt. Governor, UT J&K, e-tenders are invited on Percentage basis from approved and eligible Contractors registered with J&K Govt., CPWD, Railways and other State/Central Governments for the following works:-

S. No	Name of Work	Adv. Cost (` in lacs)	Cost of doc.t (in `)	Earnest Money (in Rs.`)	Time Allowed for completion	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7
1.	Construction of Compound Wall for Christian Graveyard at Vijaypur Reasi.	5.00	600/-	10000/-	2 Months	"C"D"
2.	Repair of Poultry Demonstration centre Reasi.	3.00	600/-	6000/-	1 Month	"D"

The Bidding documents Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Drawings, bill of quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the departmental website http://jktenders.gov.in as per below schedule:-

1	Date of Publishing of Tender Notice	01-07-2026
2	Period of downloading of bidding documents	From 01-07-2026 to 18-07-2026, 1600 Hrs
3	Bid submission Start Date	01-07-2026
4	Clarification start date	01-07-2026
5	Clarification end date	18-07-2026 up to 1600 Hrs
6	Pre-bid meeting date	16-07-2026 at 1200 Hrs.
7	Bid Submission End Date	18-07-2026 up to 1600 Hrs
8	Date & time of opening of Technical Bids (Online)	20-07-2026 on or after 1200 Hrs in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi.
9	Date & time of opening of Financial Bids (Online)	To be notified after technical bid evaluation is completed.

Position of AAA: - Accorded
Position of T. S : - Accorded
Position of Funds: - Demanded

1. Bids must be accompanied with cost of Tender document in shape of e-challan Treasury Challan indicating therein Treasury Receipt No. & date alongwith seal and Signature of the concerned Treasury, e-NIT No. and name of work duly crediting to 0059 (Revenue) favoring Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi uploading a copy of treasury challan complete in all respects and EMD/Bid Security in the shape of CDR/FDR/BG (The date of Treasury Challan/ Bid Security/Affidavits between date of start of bid submission and bid submission end date) duly pledged to Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi as mentioned in the bid documents.
2. The date and time of opening of bids shall be notified on Web Site www.jktenders.gov.in and conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-mail address.
3. The bids of Responsive bidders shall be opened online on same Web Site in the Office of Executive Engineer R&B Division, Reasi .
4. The earnest money of the unsuccessful bidder shall be released only after submission of Treasury Challan.
5. The electronic bidding system would not allow any late submission of bids after due date and time as per server time. Bidders may modify their bids by uploading their request for modification before the deadline for submission of bids. For this, the bidder need not make any additional payment towards the cost of tender document. For bid modification and consequential re- submission, the bidder is not required to withdraw his bid submitted earlier. The last modified bid submitted by the bidder within the bid submission time shall be considered as the bid. For this purpose, modification/withdrawal by other means will not be accepted. In online system of bid submission, the modification and consequential- submission of bids is allowed any number of times. The bidders may withdraw his bid by uploading their request before the deadline for submission of bids; however, if the bid is withdrawn, the re-submission of the bid is not allowed. No bid shall be modified or withdrawn after the deadline of submission of bids.
6. The date and time of opening of Financial-Bids shall be notified on Web Site www.jktenders.gov.in and conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-mail address. The Financial-bids of Responsive bidders shall be opened online in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi . The date for same shall be intimated separately.
7. The bids for the work shall remain valid for a period of 120 days from the date of opening of Technical bids.
8. The bidder shall be disqualified from bidding for any contract with this office for a period of 03 Years from the date of notification, If :-

a) Any bidder/tenderer withdraws his bid/tender during the period of bid validity or makes any modifications in the terms and conditions of the bid.
b) Failure of Successful bidder to furnish the required performance security within specified time period after issue of letter of acceptance.
c) In case contractor fails to execute the agreement within 28 days after fixation of contract.

9. Instruction to bidders regarding e-tendering process.
9.1 Bidders are advised to download bid submission manual from the "Downloads" option as well as from "Bidders Manual Kit" on website www.jktenders.gov.in to acquaint bid submission process.
9.2. To participate in bidding process, bidders have to get 'Digital Signature Certificate (DSC)' as per Information Technology Act-2000. Bidders can get digital certificate from any approved vendors.
9.3. The bidders have to submit their bids online in electronic format with digital Signature. No financial bid will be accepted in physical form.
9.4. Bids will be opened online as per time schedule mentioned above.
9.5. Bidders must ensure to upload scanned copy of all necessary documents mentioned in NIT and SBD with technical bid online.
Note: - Scan all the documents on 100 dpi with black and white option.
10. The department will not be responsible for delay in online submission due to any reasons.
Scanned copy of cost of tender document in shape of e-challan Treasury Challan indicating therein Treasury Receipt No. & date alongwith seal and Signature of the concerned Treasury, e-NIT No. and name of work duly crediting to 0059 (Revenue) favoring Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi uploading a copy of treasury challan complete in all respects and EMD/Bid Security in the shape of CDR/FDR/BG (The date of Treasury Challan/ Bid Security/Affidavits between date of start of bid submission and bid submission end date) duly pledged to Executive Engineer PWD (R&B) Division, Reasi .
11. Bidders may contact office of the Chief Engineer PW (R&B) Department, Pir Panjal or concerned Executive Engineer for any guidance for getting DSC or any other relevant details in respect of e-tendering process.
No:-2166-70 Dated:- 01-07-2026

SD/-
(Er. Pawan Kumar Bogia)
Executive Engineer
PWD (R&B) Division
Reasi

DIP/J-4930/26
Dtd: 2-7-2026

भारत में साइक्लिंग को नई रफ्तार देने की तैयारी, रक्षा खड़से ने तय किया रोडमैप

नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने गुरुवार को साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर भारत में साइक्लिंग के खेल को जमीनी स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में प्रतिभा की पहचान, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।बैठक में पुणे ग्रैंड टूर के आगामी आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि इस तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ भारत की वैश्विक खेल आयोजक के रूप में पहचान भी मजबूत करती हैं।

साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल (यूसीआई) की वार्षिक रिपोर्ट-2026 में वैश्विक साइक्लिंग के विकास में भारत के बढ़ते योगदान को विशेष रूप से सराहा गया है। रिपोर्ट में पुणे ग्रैंड टूर-2025 और भारतीय साइक्लिंग के विकास की भी प्रशंसा की गई है। बैठक में भारतीय साइक्लिंग की एक बड़ी उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया। हर्षिता जाखड़ के बाद अब भारत के पांच शीर्ष स्प्रिंटर-रोनाल्डो सिंह, एसो अल्बान, रोजित सिंह, डेविड बेकहम एलकटोचूंगो और जेम्स सिंह-सहित चार सहयोगी स्टाफ सदस्यों का चयन स्विट्जरलैंड स्थित यूसीआई वर्ल्ड साइक्लिंग सेंटर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ है। मंत्री ने इसे भारतीय साइक्लिंग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों और कोचों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं खेल विज्ञान का लाभ मिलेगा।

बैठक में खेलो इंडिया अस्मिता साइक्लिंग सिटी लीग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल देश के सबसे बड़े महिला-केंद्रित ग्रासरूट साइक्लिंग कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि इससे महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिला है और भविष्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान आसान हुई है। रक्षा खड़से ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देश का खेल तंत्र तेजी से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रासरूट व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और नियमित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी भारतीय साइक्लिस्टों को एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करेगी। बैठक में खेल अवसंरचना के विस्तार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, खेल विज्ञान के अधिक उपयोग और जिला स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों के लिए सुगम प्रगति पथ विकसित करने पर भी सहमति बनी। सरकार ने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप भारत में विश्वस्तरीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

टीवीएस मोटर की जून महीने में बिक्री 47 फीसदी बढ़कर हुई 5.90 लाख इकाई

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी की जून में कुल बिक्री सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़कर 5,90,003 इकाई हो गई। पिछले वर्ष इसी महीने यह 4,02,001 इकाई रही थी। टीवीएस मोटर ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि मोपेड सहित कुल दोपहिया वाहन की बिक्री 47 फीसदी बढ़कर 5,65,417 इकाई रही, जो जून, 2025 में 3,85,698 इकाई रही थी। घरेलू दोपहिया वाहन बिक्री जून में 46 फीसदी बढ़कर 4,11,014 इकाई रही, जबकि जून, 2025 में यह 2,81,012 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि जून महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री सालाना आधार पर 1,88,774 इकाई से 42 फीसदी बढ़कर 2,67,096 इकाई हो गई, जबकि स्कूटरों की बिक्री 53 फीसदी बढ़कर 2,47,950 इकाई हो गई, जबकि जून, 2025 में यह 1,62,291 इकाई थी। वाहन विनिर्माता कंपनी ने बताया कि उसके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री तीगुना होकर जून में 48,537 इकाई हो गई, जो जून 2025 में 14,400 इकाई थी।कंपनी ने जून के दौरान 24,586 तिपहिया वाहन भी बेचे। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय कारोबार से कुल बिक्री 47 फीसदी बढ़कर 1,72,355 इकाई रही, जबकि जून, 2025 में यह 1,17,145 इकाई थी। कंपनी की अंतरराष्ट्रीय दोपहिया वाहन बिक्री भी 48 फीसदी बढ़कर 1,54,403 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 1,04,686 इकाई थी।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला नैक पैकेजिंग का आईपीओ, पहले दिन ही दोगुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब

नई दिल्ली। इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी नैक पैकेजिंग का 439.50 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में तीन जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद छह जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि सात जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर आठ जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। शाम 3:15 बजे तक ये आईपीओ 2.21 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। यानी पहले दिन ही इस आईपीओ को दोगुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 161 रुपये से लेकर 170 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 88 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट यानी 88 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,960 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,94,480 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लॉट में 1,144 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 2,58,52,941 शेयर बेचे जा रहे हैं।

सीएसएम टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने निवेशकों को दिया झटका, फ्लैट लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

नई दिल्ली। आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सीएसएम टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 113 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 113 रुपये के स्तर पर ही हुई। लिस्टिंग होने के कुछ देर बाद ही बिकवाली के दबाव की वजह से ये शेयर गिर कर 107.35 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक गिर गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 5.65 रुपये यानी पांच प्रतिशत का नुकसान हो गया।सीएसएम टेक्नोलॉजीज के 145.78 करोड़ रुपये का आईपीओ 24 से 29 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.37 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.54 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.63 गुना सब्सक्राइब हो सका था।

ज्यादातर सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चेन्नई में सोने के भाव में तेजी का रुख

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोने के भाव में कमजोरी नजर आ रही है। भाव में आई गिरावट के कारण आज चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर दूसरे सर्राफा बाजार में सोना 1,170 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,280 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं चेन्नई में सोने के भाव में 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी दर्ज की गई है। चांदी के भाव में भी आज 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की मजबूती दर्ज की गई है। सोने की कीमत में हुए बदलाव के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,40,770 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

संगठित गिरोह का भंडाफोड़: 9 किलो सोना और 42 किलो चांदी जब्त, 8 गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में विदेशी मूल का लगभग 9 किलो सोना, 42 किलो चांदी, 700 ग्राम सोने के गहने, 8.15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और 26.67 लाख रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई है। कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने बताया कि गिरोह पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली तक अलग-अलग ट्रेनों से तस्करी कर सोना लाता था। तस्करों ने दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में सोना गलाने की अवैध इकाई भी चला रखी थी। 26 जून को डीआरआई अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन और बिहार के मंसी जंक्शन पर दो तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 2 किलो सोना मिला। इसी दिन दिल्ली में भी दो लोगों को 1.2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद

दिल्ली में अवैध सोना गलाने की इकाई का पता चला। उसी दिन एक अन्य कार्रवाई में डीआरआई ने एक महिला तस्कर को पकड़ा, जो मिजोरम के सैरांग से कोलकाता जा रही थी। उसके पास से कमरबंद में छिपाकर रखी गई सोने की 20 ईंटें मिलीं, जिनका वजन 3.3 किलो था। चेन्नई में डीआरआई ने घरेलू हवाई मालवाहक सेवा के जरिए विदेशी मुद्रा की तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा। यहां से 7,58,500 अमेरिकी डॉलर और 35 लाख थाई बाहट बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 8.15 करोड़ रुपये है। जांच में पता चला कि यह विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजी जा रही थी और इसका इस्तेमाल सोना-चांदी की तस्करी के लिए किया जा रहा था। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर डीआरआई ने एक व्यक्ति को दुबई से लौटते समय पकड़ा, जिसके पास से 1.8 किलो सोना मिला।

डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 रैली मोटर साइकिल भारत में हुई लान्च

एजेंसी

नई दिल्ली। डुकाटी कंपनी भारतीय बाजार में अपनी बाइकों की धूम मचा रहा है। कंपनी ने नई मोटरसाइकिल के तौर पर 2026 Multistrada Vy Rally को लान्च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। डुकाटी की ओर से भारतीय बाजार में हाल में ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर Duacti 2026 Multistrada Vy Rally को लॉन्च किया गया है। इस मोटरसाइकिल को एल्युमीनियम मोनोकोक फ्रेम के साथ लॉन्च किया गया है। निर्माता की ओर से Duacti 2026 Multistrada Vy Rally में 1158 सीसी की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इस मोटरसाइकिल को 170 हॉर्स पावर के साथ 123 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

ऐसे हैं फीचर्स:

Duacti 2026 Multistrada Vy Rally में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें सेमी एक्टिव सस्पेंशन, एडेप्टिव DSS EVO सिस्टम, एबीएस, व्हीली कंट्रोल, सीबीएस, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कॉर्नरिंग लाइट्स, एलईडी लाइट्स, 6.5 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 और 19 इंच स्पोक व्हील जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। डुकाटी इंडिया के प्रबंध निदेशक बिपुल चंद्र ने कहा कि 2026 मल्टीस्ट्राडा वी4 रैली डुकाटी के एडवेंचर टूरिंग दर्शन का सार प्रस्तुत करती है।

जीएसटी संग्रह जून में 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपए रहा

एजेंसी

नई दिल्ली । सकल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह जुलाई में सालाना आधार पर 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गया है। यह पिछले साल समान अवधि में 1,71,105 करोड़ रुपए पर था। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी डेटा में दी गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल सकल जीएसटी में सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) की हिस्सेदारी 37,376 करोड़ रुपए, एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) की हिस्सेदारी 45,116 करोड़ रुपए और आईजीएसटी (इंटीग्रेटिड जीएसटी) की हिस्सेदारी 1,12,320 करोड़ रुपए रही है। इसमें आयात जीएसटी से प्राप्त 60,038 करोड़ रुपए भी शामिल है। जून में जीएसटी रिफंड 32,436 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 25,121 करोड़ रुपए था। इसमें सालाना आधार पर 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिफंड को हटाकर जून में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,62,377 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जून 2025 में 1,45,984 करोड़ रुपए था। इसमें सालाना

आधार पर 11.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल जीएसटी संग्रह 6,31,699 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 5,82,542 करोड़ रुपए था। इसमें सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में सरकार ने 91,482 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है, जिससे शुद्ध जीएसटी संग्रह 5,40,218 करोड़ रुपए रह गया है। जून में जीएसटी संग्रह में शीर्ष पांच राज्यों में महाराष्ट्र (9,924 करोड़ रुपए), गुजरात (4,333 करोड़ रुपए), कर्नाटक (4,118 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (3,639 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश (3,249 करोड़ रुपए) का नाम शामिल था। इसके अतिरिक्त, आज से नौ वर्ष पहले 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया था। इसे आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। इसके चलते वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), सेल्स टैक्स जैसे कई कर समाप्त हुए और देश में एक कर व्यवस्था लागू हो सकी है, जिससे देश में कारोबार करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया।

कैबिनेट ने द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6,969.67 करोड़ रुपए के टनल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एनएच-148एई पर 6 लेन की रोड़ टनल को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के वंसतकुज में मौजूद नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस 8.1 किलोमीटर लंबी टनल को हाइब्रिड एनुटी मोड (एचएएम) पर बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 6,969.67 करोड़ रुपए होगी।

यह प्रोजेक्ट पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच आवाजाही को तेज करेगा। यह द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगा, जिससे गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट और पश्चिम दिल्ली से साउथ की ओर आने वाले ट्रैफिक को फायदा होगा। जमीन के नीचे बनने वाली ट्विन-ट्यूब टनल से जमीन के ऊपर होने वाली दिक्कतें कम होंगी और दक्षिणी रिज वन क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 1.98 किलोमीटर लंबी टनल रिज के नीचे से गुजरेगी। एनएचएआई, एम्स और महिपालपुर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव दे रहा है।

यह लिंक टनल को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से जुड़ जाएंगे। प्रस्तावित टनल रंगपुरी (दक्षिणी दिल्ली) रिज से होकर गुजरेगी। इसे ट्विन-ट्यूब टनल के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होगी और नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर-छतरपुर रोड के चौराहे से पहले खत्म होगी। बयान में कहा गया है कि इस चौराहे पर भीड़ कम करने के लिए, नेल्सन मंडेला मार्ग के साथ 1.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, मौजूदा फ्लाईओवर के साथ छतरपुर से महिपालपुर की ओर एक और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। छतरपुर की ओर राइट-टर्न ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए एक एलिवेटेड यू-टर्न का भी प्रस्ताव है।

मुख्य कैरिजवे की लंबाई 6.3 किलोमीटर है। महिपालपुर-छतरपुर रोड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर और एलिवेटेड यू-टर्न को मिलाकर, प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर हो जाती है। इसमें 3.14 किलोमीटर की टनल, 0.98 किलोमीटर का टनल अप्रोच रैंप, आरई वॉल के साथ 0.554 किलोमीटर का अप्रोच, 2.556 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा और 0.870 किलोमीटर की एट-ग्रेड रोड शामिल है।

कानपुर-कबरई एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग को मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चार लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड गलियारे की अनुमानित लागत 7145.14 करोड़ रुपये है। इसे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था भी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा बीओटी (टोल) मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही एनएच-34 के मौजूदा कानपुर-कबरई खंड का संचालन और रखरखाव भी किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकार वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे 80-100 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। कॉरिडोर कानपुर और कबरई के बीच यात्रा समय को 3.5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे (58 प्रतिशत) कर देगा। साथ ही सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा, वाहन परिचालन लागत को कम करेगा और यात्री एवं माल यातायात की कुशल आवाजाही को सुगम बनाएगा। परियोजना कानपुर और कबरई के बीच निर्बाध, उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों तक आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को मध्य प्रदेश के खनिज-समृद्ध, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक आधुनिक पहुंच नियंत्रित आर्थिक गलियारा बनेगा और इस प्रकार इसमें सुधार होगा।यह परियोजना एनएच-34, एनएच-35, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर रिंग रोड और राज्य राजमार्ग एसएच-46, एसएच-91, एसएच-10बी और एसएच-42 के साथ रणनीतिक संपर्क भी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ एकीकरण मजबूत होगा। यह कॉरिडोर कबरई खनन क्षेत्र से संपर्क को और मजबूत करेगा, खनिजों, औद्योगिक वस्तुओं, निर्माण सामग्री और कृषि उत्पादों की आवाजाही में सुधार करेगा, जिससे रसद दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, यह परियोजना 16 आर्थिक नोड से कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिनमें उन्नाव, बंथर, पंखी, रनिया, जैनपुर, रूमा, चकेरी, सुमेरपुर और भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांस गंगा इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ग्रोथ सेंटर जयपुर, कानपुर नगर नोड और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। यह 9 सोशल नोड, अर्थात् फतेहपुर, महोबा, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, बुद्ध पार्क, जेके मंदिर और जेके मंदिर से गार्डन, राधा कृष्ण मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, गोपेश्वर मंदिर और महोबा पर्यटक स्थल, और 10 लॉजिस्टिक नोड, जिनमें कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर, महोबा, कबरई, भरवा सुमेरपुर और बांदा रेलवे स्टेशन, साथ में कानपुर, चकेरी और खजुराहो हवाई अड्डे शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।

कुल मिलाकर, पीएम गतिशक्ति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में रसद प्रतिस्पर्धात्मकता, औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास में सुधार करना इसका लक्ष्य है। इस परियोजना से निर्माण के दौरान प्रति लेन प्रति किलोमीटर लगभग 11,188 प्रत्यक्ष और 13,985 अप्रत्यक्ष मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2028 तक इसकी वार्षिक औसत दैनिक यातायात (एएडीटी) लगभग 18,069 यात्री कार इकाइयों (पीसीयू) तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसके दीर्घकालिक आर्थिक, रसद और परिवहन महत्व को दर्शाता है।

रायपुर डिवीजन के 13 स्टेशनों के लिए 226 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को मंजूरी

एजेंसी

रायपुर। सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेल (एसईसीआर) के रायपुर डिवीजन के दुर्ग-तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई) प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली से बदलना शामिल है, जिससे सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। रेलवे प्रबंधन द्वारा आज जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि स्वीकृत परियोजना में रायपुर डिवीजन के दुर्ग-तारोकी खंड के मारौडा (एमएक्सए), रिसमा (आरएसए), गुंडरदेही(जीडीजेड), लाटाबोर (एलबीओ), बलोद (बीएक्सए), कुसुमकासा (केवाईएस), दल्ली राजहरा (डीआरजेड), गुडम(जीयूडीएम), भानुप्रतापपुर (बीपीटीपी), केवटी (केईटीआई), अंतागढ़ (एएजीएच), तारोकी (टीडीओके) तथा रायपुर स्टोर डिपो (आरएसडी) रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

पैनल इंटरलॉकिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में परिवर्तन से इस महत्वपूर्ण खंड पर सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का काफी आधुनिकीकरण होगा, जिससे परिचालन में अनुकूलन और सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

10 लाख से कम में नई टाटा नेक्सॉन समेत कई दमदार मॉडल जल्द देंगे दस्तक

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में एसयूवी वाहनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और वाहन निर्माता कंपनियां भी इसी मांग को देखते हुए नए मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। यदि आप कम बजट में आकर्षक डिजाइन, बेहतर प्रदर्शन और आधुनिक सुविधाओं वाली नई एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके पास कई नए विकल्प होंगे। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा और किआ जैसी कंपनियां अपनी नई एसयूवी पेश करने की तैयारी में हैं। इनमें से कई मॉडलों की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम रहने की संभावना जताई जा रही है।टाटा मोटर्स वर्ष 2027 की शुरुआत में नई पीढ़ी की नेक्सॉन को पेश कर

सकती है। माना जा रहा है कि यह वाहन मौजूदा आधार की जगह नए आधार पर तैयार किया जाएगा, जिससे अंदर बैठने वालों के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है। इसके साथ ही भविष्य में इसी आधार पर संकर तकनीक वाले मॉडल को भी बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये रखी जा सकती है।होंडा भी भारतीय बाजार के लिए नई कॉम्पैक्ट एसयूवी तैयार कर रही है। इसे वर्ष 2027 के मध्य तक पेश किए जाने की संभावना है। इस वाहन में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल सकता है। सुविधाओं की बात करें तो इसमें चालक सहायता प्रणाली, हवादार अगली सीटें, विद्युत चालित सनरूफ और आधुनिक संपर्क सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपये हो सकती है। मारुति सुजुकी वर्ष 2026 के अंत तक फ्रॉन्क्स के फ्लेक्स फ्यूल संस्करण को बाजार में उतार सकती है। यह मॉडल पूरी तरह एथेनॉल ईंधन पर चलने में सक्षम होगा।

इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के अनुरूप तैयार किया जाएगा। बाहरी डिजाइन में मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 9 लाख रुपये रहने की संभावना है।

एमएलएफएफ प्रणाली से दिल्ली-जयपुर मार्ग पर सफर होगा बाधारहित

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर स्थित मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू कर दी है। एनएचएआई ने बताया कि इस व्यवस्था से वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक तेज, सुगम और बाधारहित होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एनएचएआई ने इससे पहले 19 जून को दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली एमएलएफएफ प्रणाली शुरू की थी। मनोहरपुरा में प्रणाली लागू होने के बाद अब शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी एमएलएफएफ प्रणाली में परिवर्तित करने की योजना है। इसके बाद दिल्ली-जयपुर मार्ग पर यातायात और अधिक निर्बाध हो जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, एमएलएफएफ प्रणाली डिजिटल राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तकनीक से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय समाप्त होगा और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आएगी। नई प्रणाली के तहत बैरियर रहित टोल संग्रह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा। यह प्रणाली स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) तकनीक और फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था को एकीकृत करती है। इसके माध्यम से वाहनों से उपयोग शुल्क स्वतः वसूला जाएगा और यातायात प्रवाह प्रभावित नहीं होगा। एनएचएआई ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने की अपील की है। यदि किसी वाहन का फास्टैग अमान्य, निष्क्रिय या अपर्याप्त शेष राशि वाला पाया जाता है तो संबंधित वाहन स्वामी को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (ई-नोटिस) जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को 72 घंटे के भीतर सामान्य उपयोग शुल्क जमा करना होगा।

असम के बराक में 13 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, छह तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी

गुवाहाटी। असम पुलिस ने बराक घाटी के श्रीभूमि और कछार जिलों में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री डॉ.

हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि मादक पदार्थ तस्करों का दावा था, यह कारोबार है, लेकिन असम पुलिस का स्पष्ट जवाब था, असम में नहीं। पुलिस ने अभियान के दौरान 49,800 याबा टैबलेट और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की। जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के बजाय सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वैध आजीविका अपनाएं। उन्होंने राज्य सरकार के असम अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मप्र के मुख्यमंत्री की किसानों के हित में बड़ी घोषणा, बोले- धान की फसल पर भी देंगे भावांतर योजना का लाभ

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे हलधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर है। वे अपने अथक परिश्रम से पूरे समाज का उदर-पोषण करते हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प हैं, क्योंकि किसान समृद्ध होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। शेर की दहाड़ और सतपुड़ा के पहाड़ और अब यहां की छत्रिय धान इस क्षेत्र की बड़ी पहचान है। छत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक टैग (जीआई टैग) मिल गया है। यह हमारी देशज और पारंपरिक कृषि का वैश्विक सम्मान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना (मनरेगा का नया स्वरूप) के तहत प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कार्यम लगातार चलायें जाएंगे। किसानों और रोजगार के जरूरतमंदों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदेश के 3 हजार 941 किसानों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोदो-कुटकी के बोनस के रूप में दो करोड़ 84 लाख रुपये किसानों के खातों में अंतरित किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार श्रीअन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी दे रही है। हमने प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए अभियान शुरू किया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश के 16 हजार 754 से अधिक श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही 494 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से 629 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर सिवनी जिले को बड़ी सौगात दी। इसमें 349.33 करोड़ रुपये की लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 144.83 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बालाघाट से सिवनी तक फोरलेन रोड निर्माण कार्य की घोषणा करते हुए कहा कि जिले के छपारा ब्लॉक के ग्राम चमारी में शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। ग्राम सागर से खटकर तक पक्की रोड का निर्माण किया जाएगा। ग्राम छिड़िया पलारी में नगर वन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सिवनी जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। सभी अपने बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के ध्येय को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसी माह प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बंधुओं को यूसीसी के दायरे से पृथक रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों ने राज्य सरकार के यूसीसी प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का को गरीबों की फसल कहा जाता था। उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिये योजना शुरू कर देश-दुनिया में इसका मान बढ़ाया।

37 साल बाद नए एयर फोर्स वन की पहली उड़ान, राष्ट्रपति ट्रंप बोले- यह शानदार विमान है

एजेंसी
वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा दौरे के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी यह यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह 37 साल बाद नए सिरे से तैयार किए गए एयर फोर्स वन विमान की पहली आधिकारिक उड़ान भी थी। ट्रंप ने विमान की तारीफ करते हुए कहा कि यह 'शानदार विमान' है और इस उड़ान ने उनके दौरे को और भी खास बना दिया। ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समय) को नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में समर्थकों को संबोधित करते हुए सबसे पहले एयर फोर्स वन का जिक्र किया और फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, '37 साल बाद एयर फोर्स वन नाम के इस विमान की यह पहली आधिकारिक उड़ान थी। यह एक बेहतरीन विमान है। डग बर्गम और बाकी सभी लोगों के साथ यात्रा काफी अच्छी रही। इस दौरान हमने थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में भी काफी चर्चा की, क्योंकि वह वास्तव में बेहद खास व्यक्ति थे। ' राष्ट्रपति ने कहा कि वह दौरा उनके लिए इसलिए भी खास था, क्योंकि वह ऐसे अमेरिकी नेता को सम्मान देने पहुंचे थे, जिन्हें वह लंबे समय से अपना आदर्श मानते हैं।

नेपाल के विदेश मंत्री का बयान- 'खराब मौसम के कारण भारतीय हेलीकॉप्टर ने किया नेपाली हवाई क्षेत्र में प्रवेश'

काठमांडू । नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने साफ किया है कि 10 जून को पश्चिमी सीमावर्ती जिले धारचूला में नेपाल के हवाई क्षेत्र में देखे गए भारतीय हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम की वजह से नेपाली सीमा में प्रवेश किया था। एक बैठक में अपने मंत्रालय से जुड़े मौखिक सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाली सरकार को जानकारी मिली थी कि खराब मौसम का सामना करने के बाद भारतीय हेलीकॉप्टर धारचूला जिले में दाखिल हुआ था। उन्होंने कहा, 'संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि भारतीय हेलीकॉप्टर जानबूझकर या किसी गलत इरादे से नेपाली सीमा में दाखिल हुआ था। ' उन्होंने बताया, 'इलाके की भौगोलिक स्थितियों और मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नेपाली सीमा में दाखिल हुआ। इस मामले को लेकर संबंधित नेपाली अधिकारियों और भारतीय पक्ष के बीच जरूरी तालमेल और बातचीत हो रही है। ' नेपाली अधिकारियों के अनुसार, 10 जून को बिना इजाजत भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर के नेपाली सीमा में काफी अंदर तक उड़ान भरने से नेपाल के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ। बाद में हेलीकॉप्टर नेपाल के हवाई क्षेत्र में कुछ देर रहने के बाद भारतीय सीमा में लौट गया।

कांगो में इबोला के मामले 1,400 के पार, मरने वालों की संख्या 438 हुई

किंशासा । कांगो में इबोला संक्रमण का प्रकोप जारी है। अब तक 1,400 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 438 लोगों की मौत हो गई। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कांगो में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 1,406 हो गई है। अब तक 192 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 609 अन्य का इलाज जारी है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस प्रकोप को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' घोषित किया है। इबोला संक्रमण मुख्य रूप से पूर्वी प्रांतों इतुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु में फैला हुआ है, जहां निगरानी, मेडिकल देखभाल और बचाव के काम लगातार जारी हैं। सरकार ने कहा कि वाहनों और एम्बुलेंस की तैनाती, दवाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की आपूर्ति, जन-जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की कोशिशों के जरिए प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। कांगो ने मई के मध्य में इस प्रकोप की घोषणा की थी। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि असुरक्षा, लोगों की आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और संपर्क में आए लोगों की पहचान में लापरवाही इस बीमारी पर नियंत्रण के प्रयासों को कठिन बना रही है।

अमेरिका के 250वें सालगिरह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप बोले- देश को सबसे पहले रखना है

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमेरिका की 250वीं सालगिरह से पहले उनकी सरकार का मुख्य संदेश क्या होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की शुरुआत के आदर्शों को उसके भविष्य के लिए एक गाइड के तौर पर दिखाया। मेडोरा में समर्थकों के सामने बुधवार (स्थानीय समय) को राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार थियोडोर रूजवेल्ट की जिंदगी और प्रेसिडेंसी को देश के आने वाले 50 साल पूरे होने से जोड़ा और अमेरिकियों से हिम्मत, लक्ष्य और देशभक्ति अपनाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'जैसे ही हम अपने 250वें साल में कदम रख रहे हैं, अमेरिकियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐतिहासिक और हीरो हैं। ' राष्ट्रपति ट्रंप ने रूजवेल्ट को एक ऐसा नेता बताया, जिनकी जिंदगी उन मूल्यों को दिखाती थी जिन्होंने अमेरिका को बनाया। उन्होंने कहा, 'आज, हम अमेरिका के दिल में एक ऐसे आदमी को श्रद्धांजलि देने आए हैं।

चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगेः राष्ट्रपति ट्रंप

एजेंसी
वाशिंगटन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपे जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। ट्रंप ने दोहराया कि उनकी सरकार इस अहम जलमार्ग पर चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में बुधवार (स्थानीय समय) को राष्ट्रपति ट्रंप ने नहर के कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए पूर्व प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट की तारीफ की और इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक बताया। ट्रंप ने कहा, 'अब चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहर का नियंत्रण ट्रांसफर करने के अमेरिका के फैसले की अपनी पुरानी आलोचना दोहराई और कहा कि यह एक गलती थी। उन्होंने कहा, 'हमने इसे दे दिया। यह अब तक की सबसे महंगी चीज थी जो हमने बनाई थी और यह अब तक की सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज भी थी।' उन्होंने यह भी दावा किया कि नहर का नियंत्रण लेने के बाद पनामा ने ट्रांजिट फीस में तेजी से बढ़ोतरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'उन्होंने जो पहला काम किया, उन्होंने जहाजों की कीमतें चार गुना बढ़ा दीं और उन्हें एक भी जहाज नहीं खोना पड़ा। और फिर उन्होंने इसे दो बार और बढ़ाया, और उन्हें एक भी जहाज नहीं खोना पड़ा।' राष्ट्रपति ने रूजवेल्ट की विरासत पर चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का नेतृत्व संरक्षण और घरेलू सुधारों से आगे बढ़कर पनामा नहर सहित बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक फैला हुआ था। ट्रंप ने नहर के बारे में किसी नई पॉलिसी या कार्रवाई की घोषणा नहीं की।पनामा नहर को अमेरिका ने 20वीं सदी की शुरुआत में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के समय बनवाया था। 1977 में हस्ताक्षर किए गए संधि के तहत, अमेरिका ने धीरे-धीरे नहर का कंट्रोल पनामा को ट्रांसफर कर दिया और 31 दिसंबर, 1999 को यह हैंडओवर पूरा हुआ। नहर को पनामा कैनाल अथॉरिटी चलाती है, जो पनामा सरकार की एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। 82 किमी लंबी यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जो दुनिया भर के समुद्री व्यापार का लगभग पांच फीसदी हिस्सा ढोता है। यह अंतरराष्ट्रीय कॉमर्स के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है, जिसमें भारत के साथ होने वाला व्यापार भी शामिल है, जहां शिपिंग लागत में बदलाव या नहर यातायात में रुकावट से माल ढुलाई की दरों और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा नीति में बदलाव का दिया संकेत

एजेंसी
वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अब यह द्वीपीय देश हमारी ओर आ रहा है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनका इशारा किस बदलाव की ओर था और न ही क्यूबा को लेकर किसी नई अमेरिकी नीति का ऐलान किया। बुधवार (स्थानीय समय) को नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह टिप्पणी की। उनका यह बयान उस समय आया, जब वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा कर रहे थे। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा, 'क्यूबा की बात करें तो कई दशकों बाद अब वह हमारी ओर आ रहा है।' हालांकि उन्होंने इसके आगे कोई विस्तार नहीं दिया और यह भी नहीं बताया कि क्यूबा के साथ अमेरिका के संबंधों में किस तरह का बदलाव संभव है। ट्रंप ने यह टिप्पणी थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति की सराहना करते हुए की। उन्होंने कहा कि रूजवेल्ट के दौर में अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण और स्पेन-अमेरिका युद्ध के बाद दुनिया में अपना प्रभाव काफी बढ़ाया था। उन्होंने याद दिलाया कि उस युद्ध के बाद स्पेन ने क्यूबा, गुआम, फिलीपींस और प्यूर्टो रिको पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने क्यूबा के हमारी ओर आने वाली टिप्पणी की। हालांकि कार्यक्रम का मुख्य विषय थियोडोर रूजवेल्ट की विरासत था, लेकिन ट्रंप ने अपने भाषण में पनामा नहर, ईरान, आव्रजन (इमिग्रेशन), अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ जैसे कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

ऑस्ट्रिया में 'गुरुकुल डिप्लोमेसी': भारतीय राजदूत ने बच्चों को सुनाई पंचतंत्र की कहानियां

एजेंसी
वियना । 'रंगा सियार,' 'मूर्ख शेर और चालाक खरगोश,' 'प्यासा कौवा' और ऐसी ही भारत की मिट्टी में रची बसी और नेक नियती का पाठ पढ़ाती 'पंचतंत्र की कहानियां' ऑस्ट्रिया के बच्चे पढ़ पाएंगे। इस अभूतपूर्व पहल का अगुवा वियना स्थित भारतीय दूतावास है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की सोच वाली इस कोशिश को 'गुरुकुल डिप्लोमेसी' नाम दिया गया है। इसी पहल के तहत ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने वियना के एक स्कूल में बच्चों को प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'पंचतंत्र' की कहानियां सुनाईं। ऑस्ट्रिया स्थित भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। दूतावास ने बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रियाई स्कूली बच्चों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया गया। इसी पुस्तक के माध्यम से भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने छात्रों को पंचतंत्र की रोचक और प्रेरक कहानियां पढ़कर सुनाईं। दूतावास ने

अपने पोस्ट में लिखा, 'गुरुकुल डिप्लोमेसी के तहत भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने वियना में स्कूली बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाईं। भारतीय दूतावास ने हाल ही में ऑस्ट्रियाई छात्रों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा संस्करण प्रकाशित किया है।' पोस्ट के साथ कार्यक्रम की झलकियां और छात्रों की प्रतिक्रियाओं का वीडियो भी साझा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कहानियों को उत्साह के साथ सुना और भारतीय लोककथाओं में गहरी रुचि दिखाई। वीडियो में कई छात्र पंचतंत्र की कहानियों से मिली सीख और उनके रोचक पात्रों के बारे में अपने विचार साझा करते नजर आए।

दूतावास ने बताया कि यह पहल वियना शहर (सिटी ऑफ वियना) और स्थानीय स्कूलों में चल रहे 'बाउंस बैक' परियोजना के साथ सफल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। 'स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र' शीर्षक से शुरू की गई इस वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला में प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई पॉडकास्टर थॉमस ब्रेजिना जर्मन भाषा में पंचतंत्र की कालजयी कहानियों का रोचक अंदाज में वर्णन करेंगे। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रियाई बच्चों को भारतीय साहित्य, नैतिक मूल्यों और लोककथाओं से परिचित कराना है।

भारत ने प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दर्ज कराई आपत्ति

एजेंसी
वाशिंगटन । भारत अगले सप्ताह अपने निर्यात पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ समन्वित तरीके से चुनौती दे रहा है। सरकारी अधिकारियों और प्रमुख उद्योग संगठनों का कहना है कि जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) को लेकर वॉशिंगटन के निष्कर्ष कानूनी रूप से कमजोर हैं, पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं और इनसे दुनिया की सबसे बड़ी तथा पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह चुनौती 8 जुलाई को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ऑफिस (यूएसटीआर) की सेक्शन 301 कमेटी के सामने पेश की जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) की पूर्णिमा शेनॉय और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की शुचिता सोनालिका पैनल 8 के दौरान गवाही देंगी। पैनल 9 में उनके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डॉ. बृज मोहन और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के शुभम अरोड़ा होंगे। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के डायरेक्टर जनरल विनी मेहता 9 जुलाई को गवाही देंगे।

यह सुनवाई यूएसटीआर के उस प्रस्ताव के बाद हो रही है जिसमें सेक्शन 301 की जांच के तहत भारत से आयात पर 12.5 फीसदी की अतिरिक्त ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। यह जांच इस बात की जांच करेगी कि क्या देश जबरदस्ती मजदूरी से बनाए गए सामान के निर्यात पर रोक लगाते हैं और उसे असरदार तरीके से लागू करते हैं। आखिरी फैसला लेने से पहले यह प्रस्ताव पब्लिक कमेंट्स के लिए खुला है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यूएसटीआर के नतीजों को खारिज कर दिया है। अपनी रिपोर्ट में, मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एक मजबूत घरेलू कानूनी सिस्टम है जो एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाता है, जिसमें कानूनी रोक, संस्थागत प्रणाली और जबरदस्ती मजदूरी की कमजोरी को कम करने के मकसद से चल रहे पॉलिसी उपाय शामिल हैं। ' भारत का यह भी तर्क है कि इस बात के पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं हैं कि भारत की आयात व्यवस्था अमेरिकी व्यापार पर कोई अनुचित बोझ डालती है या उसे प्रतिबंधित करती है, जबकि सेक्शन 301 के तहत कार्रवाई करने के लिए इस तरह के प्रमाण होना आवश्यक है।कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ एक विस्तृत कानूनी और आर्थिक मामला बनाया है। सीआईआई का कहना है कि यूएस ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत भारत का पॉलिसी फ्रेमवर्क गलत या भेदभावपूर्ण नहीं है।

वेनेजुएला में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' की प्रशंसाः भूकंप पीड़ित बोले, 'भारत की स्वास्थ्य सेवा बेहतरीन'

एजेंसी
कराकस । वेनेजुएला में भारत की स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल टीम की वहां के नागरिक दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। आर्मी फील्ड अस्पताल में हो रही देखभाल और मदद को बेहतरीन बता रहे हैं। दिन रात पीड़ितों की सेवा में रत स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों के समर्पण और सेवा भाव को दिखाती तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। जन कल्याण को समर्पित स्वास्थ्य योद्धाओं की झलकियां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर साझा की। इनमें से एक वीडियो क्लिप में अपनी परिजन को लेकर पहुंची महिला ने कहा, 'हम इन्हें यहां ला-गुएरा से लेकर आए हैं। जैसे ही यहां पहुंचे हमें तुरंत मदद पहुंचाई गई। वेनेजुएला में आए भूकंप में ये घायल हो गई थीं। यहां जांच के बाद बताया गया कि डबल फिबुला फ्रैक्चर हो गया है। अब कहा गया है कि इनकी यहीं पर सर्जरी होगी। यहां व्यवस्था बहुत

अच्छी है, स्वास्थ्य सेवा बेहतरीन है।' कई तस्वीरों में स्वास्थ्यकर्मी तिमारदारी करते देखे जा सकते हैं। एमईए ने अपनी पोस्ट में इसे 'हीलिंग लाइफ, सर्विंग ह्युमैनिटी' कहा है।

24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में बुधवार तक 2,295 लोगों के मारे जाने की पुष्टि वेनेजुएला स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय मीडिया को दी। इस भूकंप से देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मची। इसके बाद भारत ने राहत और बचाव में मदद के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया।

भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री रविवार को वेनेजुएला पहुंच गई, जिसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि भारत की फील्ड अस्पताल यूनिट, राहत सामग्री, दवाइयां, और मेडिकल उपकरण वहां चल रहे राहत कार्यों को और मजबूत करेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत की सहायता वेनेजुएला पहुंच गई है। हमें भरोसा है कि फील्ड अस्पताल यूनिट, राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण वहां भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्यों को और मजबूती देंगे। ' कोटे डी आइवर में भारतीय दूतावास ने भी 'एक्स' पर जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि भारतीय वायुसेना के दो सी-17 विमान अबिदजान होते हुए वेनेजुएला पहुंचे।

दक्षिण कोरियाः जानलेवा घटना के बाद सेना ने रिजर्व सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए सुरक्षा-मेडिकल इंतजाम बढ़ाने का किया वादा

एजेंसी
सियोल । मई में सियोल के उत्तर में रात के समय हुई एक ड्रिल के दौरान एक रिजर्व सैनिक की मौत के बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने गुरुवार को नियमित रिजर्व सैनिक ट्रेनिंग के लिए सुरक्षा और मेडिकल उपायों को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस मामले की गहन जांच के बाद सेना ने कहा कि 20-30 साल की उम्र के रिजर्व सैनिक की मौत ट्रेनिंग से अलग, पहले से मौजूद मेडिकल समस्याओं के कारण हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसी ड्रिल के लिए सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की कोशिश करने का वादा भी किया। 13 मई को सियोल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में पोचेओन में तीन दिन की रिजर्व सैनिक ट्रेनिंग के दौरान एक रिजर्व सैनिक रात की ट्रेनिंग वाली जगह पर जाते समय बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रिजर्व सैनिक ट्रेनिंग के पूरे मैनेजमेंट की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई और ऐसी अटकलें लगने लगीं कि इंस्ट्रक्टर ने अलग-अलग प्रतिभागियों की सेहत का ध्यान रखे बिना ही ड्रिल जारी रखी।

सेना ने कहा कि जांच में पता चला है कि रिजर्व सैनिक की मौत पैंक्रियाटाइटिस के कारण हुई थी, जो पहले से मौजूद एक बीमारी थी और जिसका इलाज वह लंबे समय से करवा रहा था। सेना के एक अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हमने दो स्वतंत्र फोरेंसिक कंसल्टेशन एजेंसियों से प्रोफेशनल राय मांगी थी और इस बात की पुष्टि हुई है कि पहले से मौजूद मेडिकल समस्या का सीधा संबंध मौत के कारण से था। ' अधिकारी ने रिजर्व सैनिक की मौत से जुड़ी कई अफवाहों को खारिज कर दिया, जिसमें यह अटकल भी शामिल थी कि डिवीजन कमांडर सैनिकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे।

कनाडा में मौसम की दोहरी मारः कहीं गर्मी तो कहीं बाढ़ से लोग तबाह

एजेंसी
टोरंटो । कनाडा मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। देश के बड़े हिस्से में 'हीट डोम' के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भीषण गर्मी के चलते लाखों कनाडाई नागरिक हीट अलर्ट के दायरे में हैं। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा ने ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेयरी क्षेत्र और नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज के कई हिस्सों के लिए हीट वार्निंग जारी की है। इन इलाकों में दिन का तापमान और उमस सामान्य से काफी अधिक दर्ज की जा रही है। ओंटारियो सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में शामिल है, जहां लंबे समय से गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी ओंटारियो के कई इलाकों में दिन के समय तापमान लगातार

ऊंचा बना हुआ है और रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। वहीं, पूर्वी ओंटारियो के निवासियों को दिन के सबसे गर्म समय में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, मौसम विभाग ने हीट अलर्ट वाले क्षेत्रों के लोगों से पर्याप्त पानी पीने, दोपहर के समय कठिन शारीरिक गतिविधियों से बचने और बुजुर्गों, छोटे बच्चों तथा अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उधर, भीषण गर्मी और अस्थिर मौसम के संयुक्त प्रभाव से कई क्षेत्रों में तेज आंधी-तूफान और उससे जुड़ी अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। राजधानी ओटावा में कनाडा दिवस के समारोह भी खराब मौसम की भेंट चढ़ गए। भारी तूफान और स्थानीय स्तर पर आई बाढ़ के कारण दोपहर के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इनमें स्नोबर्ड्स एरोबैटिक टीम का बहुप्रतीक्षित फ्लाईपास्ट भी शामिल था।

वहीं, देश के मध्य भाग में स्थित मैनिटोबा के पार्कलैंड क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत में हुई मूसलाधार बारिश ने गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। पश्चिमी मैनिटोबा के डॉफिन शहर में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए स्थानीय आपातकाल घोषित कर दिया गया।

यूएन महासभा ने एक बार फिर भारत के प्रस्तावित आतंकवाद कन्वेंशन को अपनाने का किया आग्रह

एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक बार फिर भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 मतों के समर्थन और तीन मतों के विरोध से पारित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (जीसीटीएस) की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने के लिए 'हरसंभव प्रयास' करने का आग्रह किया। नई दिल्ली द्वारा 31 वर्ष पहले पेश किए जाने के बावजूद यह अब तक लंबित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने चेतावनी दी कि 'सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचे' के अभाव ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमजोर किया है।

सीसीआईटी को अपनाने में आ रही दो प्रमुख बाधाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि आतंकवाद का प्रभावी मुकाबला अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए तभी संभव है, जब 'दोहरे मानदंड न हों' और 'अच्छे तथा बुरे आतंकवादियों' के बीच कोई भेदभाव न किया जाए।

सीसीआईटी का विरोध पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की ओर से किया जाता रहा है। ये देश आतंकवादियों के बीच भेद करने की कोशिश करते हैं और कुछ को 'स्वतंत्रता सेनानी' का जामा पहनाकर आतंकवाद के समर्थन को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं।

हरीश ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दोहरे मानदंडों को पूरी तरह खारिज करना होगा। '

उन्होंने कहा, 'आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की शिकायत, राजनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक गणना के बावजूद आतंकवाद को उसके हर रूप और अभिव्यक्ति में बिना किसी शर्त के निंदा की जानी चाहिए। '

उन्होंने कहा, 'आतंकवादी घटनाओं के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना सभी की जिम्मेदारी है। सदस्य देशों को इस दिशा में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। '

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से सात लोगों की मौत

एजेंसी
इस्लामाबाद । पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सैफुल्लाह झील पर पर्यटकों से भरी नाव के पलट जाने से सात लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया। एक जिला पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बुधवार को स्वात जिले के सुंदर कलाम इलाके में एक ही परिवार के आठ सदस्यों को लेकर घूमने निकली नाव पलट गई। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बचाव दल, पुलिस अधिकारी और स्थानीय स्वयंसेवक लापता व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए हैं।स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि इससे पहले मंगलवार को लाहौर के कैना इलाके में एक प्राइवेट ट्यूशन एकेडमी की छत गिरने से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।मौतों की संख्या की पुष्टि करते हुए, पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि मलबे में करीब 20 लोग फंसे हुए थे, जिनमें वे 14 बच्चे भी शामिल थे जिन्हें कैना तहसील मुख्यालय (टीएचक्यू) अस्पताल में मृत लाया गया था। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद, रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने कहा कि एक महिला टीचर और आठ बच्चों को कई चोटों के साथ लाहौर जनरल हॉस्पिटल (एलजीएच) में भर्ती कराया गया।

ईरान-अमेरिका के बीच दोहा में हो रही अगले चरण की वार्ता, उपराष्ट्रपति वेंस बोले- 'अच्छी चल रही है बातचीत'

एजेंसी
वाशिंगटन । अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा में ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया या कमर्शियल शिपिंग पर हमला किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सैन्य बल का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे। वर्जीनिया में नेवल एयर स्टेशन ओशियाना का दौरा करने के बाद बुधवार (लोकल टाइम) को एयर फोर्स टू से रवाना होने से पहले वेंस ने मीडिया से कहा कि ईरानी टारगेट्स के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी सैन्य एक्शन के बाद अमेरिका, ईरान, कतर और दूसरे देशों के नेगोशिएटर्स अगले चरण को लेकर चर्चा कर रहे थे। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, 'अभी बातचीत करने वाले ईरानियों, कतरियों और दोहा में दूसरों के साथ बैठे हैं। अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन बातचीत अच्छी चल रही है। ' उन्होंने कहा कि अभी का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कमर्शियल शिपिंग इस इलाके से सुरक्षित रूप से चलती रहे। उन्होंने कहा, 'कमर्शियल ट्रैफिक सच में, यह पहले ही एक शानदार दिशा में शुरू हो चुका है। अब हमारे पास तेल 68 डॉलर पर है। गैस की कीमतें कम होने लगी हैं। हम परमाणु मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। हम इस बारे में बात करना शुरू करने जा रहे हैं। ' वेंस ने कहा कि ट्रंप सरकार बातचीत जारी रखेगा लेकिन, अगर ईरान अपना रास्ता बदलता है तो सैन्य विकल्प मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा, 'मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रपति हमारी मिलिट्री को तब तक वापस नहीं भेजेंगे, जब तक उन्हें ऐसा करना जरूरी न हो, जब तक इसका कोई साफ मकसद न हो। अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वे फिर से कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा हिसाब बदल जाएगा। '

ईरानी नेतृत्व में मतभेद के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेहरान के अंदर पश्चिम और पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए समर्थन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'ईरान की व्यवस्था में, दुनिया के कई अन्य देशों की तरह, ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि पिछले 47 वर्षों की सरकारी नीतियां एक गलती रही हैं और अब अमेरिका, यूरोप तथा खाड़ी के अरब देशों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग अब भी पुरानी सोच और पुराने तौर-तरीकों से जुड़े हुए हैं। ' उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का मानना है कि हम उन लोगों के लिए बहुत मोमेंटम देखते हैं जो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वह डिप्लोमेसी को जितना हो सके सफल होने का मौका देते रहेंगे। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि ईरान की तरफ से संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करने या अंतरराष्ट्रीय निगरानी पर रोक लगाने की कोई भी कोशिश अमेरिका के अलग जवाब को शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के कमेंट्स के बारे में पूछे जाने पर वेंस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अंदाजा लगाने से भी मना कर दिया और कहा, 'मैं 2028 के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मेरा नजरिया यह है कि चलो अभी अच्छा काम करते हैं। चलो अमेरिकी लोगों के लिए कुछ जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भविष्य आएगा तो हम भविष्य की चिंता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में वेंस ने कहा कि उनका मानना है कि जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने हाल ही में बर्थराइट सिटिजनशिप के फैसले में गलती की है। कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं और सरकार उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगी।

page 3- and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/3/2026 12:42 AM Page 2

डोर-टू-डोर मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य जांच, परामर्श और नेत्र परीक्षण की सुविधा, ग्रामीणों को मिला राहत का लाभ

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। अखनूर के मिलन दी खुई गांव में डोर-टू-डोर मेडिकल कैंप का आयोजन कर ग्रामीणों को उनके घरों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। इस पहल के तहत सेना की समर्पित चिकित्सा टीम ने घर-घर जाकर लोगों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श तथा नेत्र जांच की। मेडिकल कैंप का उद्देश्य विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और उन लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था जिन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर-घर जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार और चिकित्सकीय सलाह मिल सकी।

भारतीय सेना की इस पहल ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया बल्कि सामुदायिक सेवा की भावना को भी मजबूत किया। ग्रामीणों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। भारतीय सेना ने इस अवसर पर दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सेना ने समाज की सेवा में समर्पित सभी चिकित्सकों और चिकित्सा टीमों के योगदान को भी सम्मानपूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

केवीके सांबा का 30 दिवसीय 'खेत बचाओ अभियान' ऐतिहासिक जनभागीदारी के साथ संपन्न

सांबा। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) सांबा, SKUAST-Jammu ने अपना 30 दिवसीय *खेत बचाओ अभियान (केबीए) 2026 सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अभियान ने कृषि प्रसार के क्षेत्र में अभूतपूर्व जनसंपर्क और रिकॉर्ड तोड़ जनभागीदारी के साथ एक नया इतिहास रच दिया। पूरे जिले में हजारों किसानों, महिला किसानों, ग्रामीण युवाओं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे यह केवीके सांबा द्वारा अब तक चलाए गए सबसे व्यापक कृषि जागरूकता अभियानों में से एक बन गया।

यह अभियान प्रो. बी. एन. त्रिपाठी, कुलपति, स्कूास्ट-जम्मू के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रो. अमरीश वैद, निदेशक प्रसार, स्कूास्ट-जम्मू के मार्गदर्शन तथा प्रो. (डॉ.) संजय खजूरिया, मुख्य वैज्ञानिक (कृषि वानिकी) एवं प्रमुख, केवीके सांबा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया।

एक माह तक चले इस अभियान के दौरान केवीके सांबा ने जिले के विभिन्न विकास खंडों तथा सीमावर्ती गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन, किसान-वैज्ञानिक संवाद, व्यावहारिक प्रशिक्षण, ग्राम सभाएं तथा विभिन्न कृषि प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच टिकाऊ, जलवायु-अनुकूल तथा लाभकारी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था।

अभियान के दौरान कृषि वानिकी को एक टिकाऊ भूमि उपयोग प्रणाली के रूप में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। किसानों को कृषि फसलों के साथ उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

इसके साथ ही अच्छी कृषि पद्धतियों (गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज) को अपनाने पर भी विशेष बल दिया गया, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता मिल सके। किसानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को उच्च मूल्य वाली आय का स्रोत बताते हुए इसके प्रति जागरूक किया गया। बागवानी करने वाले किसानों को बागों में अंतरवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) अपनाने के लाभों की जानकारी दी गई, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग और अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके।

अभियान के दौरान बागवानी एवं सब्जी फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट) की वैज्ञानिक तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खाद, जैव उर्वरकों तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित एवं संतुलित उपयोग के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। उन्हें अनुशंसित मात्रा, सही छिड़काव तकनीक, प्रतीक्षा अवधि, सुरक्षा उपायों तथा समेकित कीट प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि कीटनाशकों के अवशेषों और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके।

अभियान के दौरान वैज्ञानिक जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों एवं कृषि प्रसार पद्धतियों का प्रभावी उपयोग किया गया। समूह बैठकें, व्यावहारिक प्रदर्शन, संवाद कार्यक्रम, खेत भ्रमण, किसान-वैज्ञानिक बैठकें तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकों को सरल एवं किसान हितैषी तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाया गया।

केवीके सांबा ने जैव उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया तथा किसानों को इनके माध्यम से मिट्टी की सूक्ष्मजीव गतिविधियों में सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसानों को मिट्टी की जांच एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह भी दी गई।

अभियान के सफल समापन पर प्रो. (डॉ.) संजय खजूरिया ने किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता किसानों के वैज्ञानिक कृषि के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केवीके सांबा भविष्य में भी किसान केंद्रित कार्यक्रमों एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों में सत शर्मा, सांसद तथा विधायक सी. पी. गंगा, डॉ. डी. के. मन्याल और एस. एस. सलाथिया ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त पूर्व डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त, पूर्व डीडीसी सदस्य, पूर्व बीडीसी चेयरमैन तथा पूर्व बीडीसी सदस्यों ने भी अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई।इस अभियान की सफलता में केवीके सांबा की वैज्ञानिक टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टीम में डॉ. नीरजा शर्मा (मुख्य वैज्ञानिक, बागवानी), डॉ. सौरव गुप्ता, डॉ. अजय कुमार तथा डॉ. शालिनी खजूरिया ने विभिन्न गतिविधियों के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए वैज्ञानिक तकनीकों एवं कृषि संबंधी सिफारिशों को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया।

स्थानीय समाचार

आदित्य बिरला ज्वैलरी के इंद्रिया ने सबसे चमकीले हीरों के साथ उद्योग में नए मानदंड पेश किये

मुंबई, 02 जुलाई। आदित्य बिरला ज्वैलरी के ब्रांड इंद्रिया ने प्राकृतिक हीरों के चयन में एक उद्योग-प्रथम मानक स्थापित किया है, जिससे हीरा खरीदने के अनुभव में और ज़्यादा आनंद और भरोसा जुड़ गया है। इस भरोसे के साथ कि असाधारण चमक ही हीरे की गुणवत्ता की सबसे साफ दिखने वाली पहचान है, यह तरीका ब्रांड के सर्वश्रेष्ठ चयन मानकों पर आधारित है।

पारंपरिक ग्रेडिंग मानकों को छोड़कर, इंद्रिया हीरों को परखने और चुनने के लिए एक नया तरीका अपनाता है। वे मुख्य रूप से यह देखते हैं कि कोई हीरा रोशनी को कितनी अच्छी तरह समेटता है, फैलाता है और उसे वापस लौटाता है, ताकि उससे सबसे बेहतरीन चमक और झिलमिलाहट मिल सके। इस कड़े टेस्ट में हर 5 असली हीरों में से केवल 1 हीरा ही पास हो पाता है।

अमरनाथ यात्रियों के लिए सात्विक भोजन की विशेष व्यवस्था, एकादशी व्रतधारियों के लिए अलग प्रबंध

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के उद्देश्य से अखिल भारतीय धर्म प्रचार सेवा समिति जम्मू-कश्मीर द्वारा आयोजित 10वें विशाल भंडारे का शुभारंभ गुरुवार को धार्मिक विधि-विधान के साथ किया गया। भंडारे का उद्घाटन दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 आचार्य बंसीदास जी महाराज ने समिति के राष्ट्रीय समन्वयक सुनील शर्मा की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन, वैदिक मंत्रोच्चारण और ऊबम-बम भोलेऊ के जयघोष के साथ हुई।

इस अवसर पर डीबीपीएस के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, सनातन धर्म सभा के पूर्व अध्यक्ष जगदीश डोगरा तथा जीसीपीएफ के यश पाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय समन्वयक सुनील शर्मा ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को पूरे समय स्वच्छ, स्वादिष्ट, ऊर्जा प्रदान करने वाला तथा आसानी से पचने वाला सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से विशेष भोजन की व्यवस्था भी की गई है। समिति के प्रवक्ता स्वतंत्र बख्शी ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों

के लिए पर्याप्त भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि समिति पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ यात्रियों की सेवा में जुटी हुई है तथा बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से यह सेवा निरंतर जारी रहेगी।

'1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या के सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाए'

श्रीनगर, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर भाजपा इकाई ने गुरुवार को मांग की कि अप्रैल 1990 में युवा कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या के सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाए और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाए।

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि भट कश्मीर की बेटी थीं और उन्होंने कश्मीर की मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि उन्हें, उनके परिवार को, समुदाय को और पूरे कश्मीर को न्याय के लिए 36 साल इंतजार करना पड़ा। न्याय अधूरा है, यह अपूर्ण है। उनका हत्यारा पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि जब उसे यहां लाया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा तभी न्याय पूरा होगा।

जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने सोमवार को 700 से अधिक पृष्ठों की आरोपपत्र दाखिल की जिसमें प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को अप्रैल 1990 में आतंकवादियों द्वारा भट के अपहरण और क्रूर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने इसे आतंकवाद के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक ऊऐतिहासिक मील का पत्थरऊ बताया।

एसआईए जिसने 2024 में मामला सौंपे जाने के बाद इसे फिर से खोला ने यहां नामित एनआईए अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया है।

सरला शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) सौरा में नर्स के रूप में कार्यरत थी।

सेठी ने कहा कि पूरे कश्मीरी समाज को इस मामले में अभियोजन पक्ष की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार और अभियोजन एजेंसियों से अपील करते हैं कि वे इस मामले को मजबूती से उठाएं ताकि हत्यारों को कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

छात्रों की गूंज अभियान के तहत कांग्रेस ने छात्रों से किया संवाद, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की उठाई मांग

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.) जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बुधवार को राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में करीब एक हजार छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कथित पेपर लीक, बार-बार परीक्षाएं स्थगित होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी, बढ़ती बेरोजगारी और शैक्षणिक दबाव से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर साझा कीं।

कार्यक्रम के दौरान कई छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत के बावजूद बार-बार होने वाली देरी, परीक्षाओं के स्थगन और कथित अनियमितताओं ने उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। छात्रों ने नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते मानसिक तनाव पर भी चिंता व्यक्त की। कुछ छात्रों ने महंगी कोचिंग, बार-बार परीक्षा की तैयारी और परिवारों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया।

सभा को संबोधित करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि छात्रों की मेहनत और त्याग व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को लेकर छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सपनों से समझौता नहीं किया जा सकता और प्रत्येक योग्य छात्र को निष्पक्ष परीक्षा, समयबद्ध भर्ती तथा समान अवसर मिलना चाहिए। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर के अध्यक्ष डॉ. आदिल फारूक मीर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शमीमा रैना, जम्मू-कश्मीर के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी मान सिंह राठौड़, प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता यासिर मंडू, इंजीनियर बशारत बशीर वानी, मुसद्दिक मेहराज, सैयद इकबाल, वसीम यासीन और मीर मोहम्मद यूनिस सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

मीडिया से बातचीत में कर्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस सबसे पहले नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली पार्टी थी। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू-कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है न कि केवल राजनीतिक नारा। श्री अमरनाथ यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि कश्मीर की पहचान हमेशा से अपनी मेहमाननवाजी और सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परंपरा आगे भी कायम रहेगी। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया किछात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं से लगातार संवाद जारी रखा जाएगा तथा शिक्षा सुधार, पारदर्शी भर्ती, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेके प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने प्रधान सचिव से की मुलाकात

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने निजी स्कूलों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राम निवास शर्मा से जम्मू में मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक हांडा तथा कोषाध्यक्ष संजीव लूथरा शामिल थे। बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि मान्यता और संबद्धता (रिकॉग्निशन/अफिलिएशन) के लिए जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित संयुक्त ऑनलाइन पोर्टल पिछले चार माह से उपलब्ध नहीं है जिससे निजी स्कूलों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जेकेबोस ने 30 जून 2026 तक निरीक्षण शुल्क और विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने की समयसीमा निर्धारित की थी। जबकि संबंधित विभाग समय पर एनओसी जारी नहीं कर पाए ऐसे में 30 जून के बाद निजी स्कूलों से विलंब शुल्क वसूलना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने यह भी मांग उठाई कि स्कूल शिक्षा विभाग की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए तथा विभिन्न विभागों से मिलने वाले एनओसी को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट (पीएसजीए) के दायरे में लाकर समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराई जाए ताकि छोटे निजी स्कूल संचालकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके।

प्रधान सचिव राम निवास शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग बेहतर आधारभूत सुविधाओं वाले निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईज ऑफ वर्क पहल शुरू की गई है जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संज्ञान में भी लाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इत्तू के पास विचाराधीन है और अगले कुछ दिनों में नई एवं सरल मान्यता प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

ओबीसी मोर्चा ने नौशहरा-सुंदरबनी में संगठनात्मक बैठक की, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। भाजपा ओबीसी मोर्चा जम्मू-कश्मीर यूटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म ज्योत सत्ती ने नौशहरा-सुंदरबनी जिले में संगठनात्मक बैठक आयोजित कर मोर्चे की गतिविधियों की समीक्षा की तथा संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला पदाधिकारियों, मंडल प्रतिनिधियों और मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लेते हुए संगठनात्मक कार्यों एवं पार्टी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया।

मिशन युवा के एक वर्ष पूरे होने पर जेएंडके बैंक का मेगा ऋण वितरण अभियान, 2,828 लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता

जम्मू, 02 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार की प्रमुख पहल मिशन युवा के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर जेएंडके बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश भर में मिशन युवा - मेगा डिस्बर्सल डे का आयोजन करते हुए विशेष ऋण वितरण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बैंक की विभिन्न शाखाओं ने पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए। अभियान का समापन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताव चटर्जी ने बैंक के कॉरपोरेट मुख्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक बटन दबाकर किया।

इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक आशुतोष सरीन, महाप्रबंधक (आरएएम) राकेश मगोत्रा, उप महाप्रबंधक तनवीर हुसैन और अर्जुन सिंह राठौड़ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जोनल एवं क्लस्टर प्रमुख भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

बैंक के अनुसार मिशन युवा के तहत अब तक 28,400 से अधिक मामलों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं मेगा डिस्बर्सल डे के दौरान 2,828 लाभार्थियों को ऋण राशि जारी की गई। अमिताव चटर्जी ने मिशन युवा के पहले वर्ष की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए बैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बैंक ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अब कार्यक्रम की सफलता का आकलन केवल ऋण वितरण की संख्या से नहीं बल्कि इन ऋणों के माध्यम से स्थापित होने वाले सफल और टिकाऊ उद्यमों, रोजगार सृजन तथा आजीविका के अवसरों से किया जाएगा। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के अंत तक मिशन युवा के तहत कुल 50,000 ऋण वितरण का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में प्राप्त अनुभव और संस्थागत क्षमता के आधार पर यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को पहले से वितरित ऋणों के उपयोग की नियमित निगरानी करने और उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले महाप्रबंधक (आरएएम) राकेश मगोत्रा ने मिशन युवा के तहत बैंक की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि ऋण वितरण के बाद भी लाभार्थियों के साथ निरंतर संपर्क, उनकी सहायता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बीच मिशन युवा के मिशन निदेशक हरविंदर सिंह (आईएएस) ने भी बैंक के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि जेएंडके बैंक मिशन युवा का प्रमुख क्रियान्वयन साझेदार बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि बैंक की सक्रिय कार्यशैली, समयबद्ध ऋण वितरण और उद्यमियों को निरंतर सहयोग देने की पहल ने जम्मू-कश्मीर में उद्यमिता आधारित रोजगार सृजन के सरकारी लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

योगी सरकार आने पर पकड़ी केंद्रीय योजनाओं ने रफ्तार

2017 तक एक भी जिला ओडीएफ नहीं, योगी सरकार ने बनवाए 3.31 करोड़ से अधिक शौचालय

खाली सिलेंडरों के दौर से निकलकर अब होली-दिवाली पर मुफ्त रिफिल का तोहफा

***लखनऊ, 2 जुलाई।** प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद आमजन को सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2017 से पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछली सरकारें राजनीतिक कारणों से केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में रोड़े अटकाती थीं। इतना ही नहीं, कई योजनाओं के मिलते-जुलते नाम रखकर लोगों को बरगलाने की भी चेष्टा की जाती थी। नतीजा यह कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहती थी। लेकिन, जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, केंद्र सरकार की योजनाओं पर लगे ताले खुल गए। इससे केंद्र व राज्य, दोनों सरकारों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा।

केंद्र सरकार ने देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। हालांकि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को उत्तर प्रदेश में गति देने के बजाय अपनी समाजवादी आवास योजना और लोहिया ग्रामीण आवास योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसके बाद आरोप लगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र को लाभार्थियों की सूची भेजने और मैचिंग ग्रांट (राज्य का हिस्सा) जारी करने में ढिलाई बरती।

स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2014 से 2017 तक वह सरकार 50 हजार आवास भी नहीं बना पाई। बाद में योगी सरकार आने पर इस कार्य को डबल इंजन की रफ्तार दी गई। योगी सरकार ने 9 वर्षों में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया है।

किसानों को सूखे, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लॉन्च की थी। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से भी प्रीमियम का एक हिस्सा दिया जाना था और राज्य की एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभानी थी। हालांकि 2017 से पहले की सरकार की उदासीनता के कारण करीब 3 प्रतिशत किसानों का ही बीमा हो सका था, जिससे यूपी के किसान केंद्रीय मुआवजे से वंचित रह गए। वहीं उस समय के दौरान भाजपा शासित राज्यों में जहां 60-70 प्रतिशत किसानों को इसका लाभ मिल चुका था। योगी सरकार में इस योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में 79 लाख से अधिक कृषकों को 6,283 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान किया जा चुका है।

2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन पीएम मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक था, जिसका उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। इस योजना के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए केंद्र से फंड जारी होना था, लेकिन इसके लिए राज्य को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था और अपनी हिस्सेदारी तय करनी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखाई। वह इस योजना की ब्रांडिंग के खिलाफ थी, क्योंकि वह इसे भाजपा की योजना मानती थे। नतीजा यह हुआ कि 2014-2017 के बीच यूपी में शौचालय निर्माण की गति बेहद धीमी रही और राज्य ओडीएफ रैंकिंग में काफी पीछे छूट गया।

मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश का ग्रामीण स्वच्छता दायरा महज 35 प्रतिशत के आस-पास ही पहुंच पाया था। वहीं प्रदेश का एक भी जिला पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित नहीं हो सका था।